प्रेरणा स्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ..सच

माही की गूंज

Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

बुद्धि का विकास मानव के जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए।
डॉ. बीआर अंबेड़कर

वर्ष-02, अंक -39 (साप्ताहिक) | खवासा, गुरुवार 2 जुलाई 2020 | पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

न्यूज ब्रीफ

88 की नेगेटिव व 9 की आई कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट

माही की गूंज, खरगोन

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय द्वारा बुधवार को हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया। जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 9 मरीजों की पुष्टि की गई है, इस तरह जिले में कुल 298 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है, इनमें 250 स्वस्थ्य होकर डिस्चार्ज हुए। जबकि 15 की मृत्यू तथा 33 मरीज स्थिर है। वहीं पिछले 24 घंटे में 88 सैंपलों की नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है तथा 101 नए सैंपल जांच के लिए भेजे गए है। अब 203 सैंपलों की रिपोर्ट आना शेष है।

नवनिर्मित मीडिएशन सेंटर का ई-लोकार्पण 4 जुलाई को

माही की गूंज, खरगोन

तहसील न्यायालय महेश्वर के अंतर्गत नवनिर्मित मीडिएशन सेंटर भवन का ई-लोकार्पण 4 जुलाई को प्रातः साढे 10 बजे मुख्य न्यायाधिपति अजय कुमार मित्तल एवं मुख्य संरक्षक संजय यादव द्वारा किया जाएगा। यह कार्यक्रम कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए आयोजित होगा।

आपराधिक मामलों के निर्णय के प्रकाशन से समाज में बढ़ता है न्याय के प्रति विश्वास

माही की गूंज थांदला

मीडिया सेल प्रभारी वर्षा जैन ने बताया कि, अभियोजन विभाग द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में संचालक लोक अभियोजन पुरुषोत्तम शर्मा ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के सभी जिलों के अभियोजन मीडिया प्रभारियों के कार्यों की समीक्षा की। उनके द्वारा कोरोना से स्वयं का बचाव कर अपने दायित्व का निर्वहन करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि आपराधिक मामलों के निर्णयोके प्रकाशन से समाज में न्याय के प्रति विश्वास बढ़ता है ।अपराधियों को सजा होने से समाज में किसी भी प्रकार का अपराध करने के प्रति भय उत्पन्न होता है ।संचालक शर्मा ने कहा की अभियोजन के कार्यों को मीडिया सेल के द्वारा ही जनता के बीच पत्रकारों के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है और अधिक से अधिक प्रकाशन पर बल दिया। संचालक शर्मा द्वारा अभियोजन के मीडिया सेल प्रभारियों की समस्याओं को सुनकर उनके निराकरण का आश्वासन दिया गया। जिला झाबुआ से मीडिया सेल प्रभारी वर्षा जैन सहित समस्त मीडिया सेल प्रभारी समीक्षा बैठक में उपस्थित रहे।

फर्जी डॉ. व सरगना अजीत राय के भतीजे की पीड़ित पत्नी ने वीडियो जारी कर पति के साथ तंत्र की खोली पोल

बांग्लादेशी सुर्पना राय का पति विपलब हाथ पैर बांधकर मारपीट कर करता था प्रताड़ित

माही की गूंज, संजय भटेवरा।

बांग्लादेशी उर्फफर्जी डॉक्टर किस तरह से भारत की सीमा में चोर रास्ते से दलालों के माध्यम से प्रवेश होकर छोटे-छोटे गांव में जाकर किस तरह से फर्जी रूप से ग्राम पंचायतों में अपना पंजीयन करवाकर राशन कार्ड बनवाने के साथ अपने-आप को भारतीय मूल का साबित कर सारे भारतीय मूल के दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, परिचय पत्र, समग्र आईडी के साथ नामावली में अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं, और मतदाता सुची में नाम दर्ज करवाने के साथ एक से अधिक स्थानों पर अलग-अलग राशन कार्ड बनवाकर शासन की योजनाओं का लाभ लेकर जालसाजी कर रहे हैं, वही इन्ही फर्जी दस्तावेजो के साथ फर्जी रूप से पासपोर्ट तक बनवा रहे है। इतना ही नहीं बांग्लादेश से आकर भारत में अपने परिवार के उन सदस्यों के नाम भी पंजीकृत भारत में करवा दिया जो वर्तमान में भी बांग्लादेश में ही रह रहे हैं, वरन चोर रास्ते से जिस समय दलाल के माध्यम से भी आने में परेशानी होती है उस समय बांग्लादेश के पासपोर्ट पर भारत आ रहे हैं उनके नाम भी भारत में पंजीकृत होकर नामावली तक में भी नाम दर्ज होकर भारत के पूरे सिस्टम की पोल झाबुआ जिले के खवासा में रह रहे एक ही बांग्लादेशी अजीत राय ने एक बानगी के साथ खोल दी है जिसने किस तरह से फर्जी रूप से अपने रिश्तेदारों और परिचितों के नाम फर्जी रूप से खवासा पंचायत में पंजीकृत करवाकर बांग्लादेशियों को भारतीय मूल का बना दिया और वह वर्तमान में खवासा में नहीं रहकर भी खवासा के रिकॉर्ड में आज भी दर्ज है का खुलासा किया था और माही की गूंज की यह मुहिम जब तक हमारा तंत्र व सत्ता में बैठी सरकार संज्ञान में लेकर भारतीय मूल की व्यवस्था को धूमिल करने वाले इन बांग्लादेशियों के विरुद्ध जब तक कार्यवाही नहीं होगी, जब तक यह मुहिम भी जारी रहेगी।

इसी कड़ी में आज हम उस महिला जिसका खुलासा पूर्व में कर चुके हैं कि, वह खवासा में कभी आकर रही ही नहीं लेकिन अजीत राय ने उसका नाम खवासा के रिकॉर्ड में दर्ज करवाकर खवासा का मूल निवासी बना दिया। जो कि उक्त महिला अजीत राय के भतीजे विपलब राय की बांग्लादेशी पत्नी सुर्पना है जिसका एक और खुलासा कर रहे है। बतादे कि, बांग्लादेशी सरगना अजीत राय का भतीजा पिछले कई सालो से अजीत राय के साथ बांग्लादेश से आकर पेटलावद जनपद पंचायत के ग्राम बोडायता में रह रहा है वही बोडायता में रहते हुए ही बांग्लादेश की रहने वाली एक गरिब परिवार की लडकी सुर्पना राय से विवाह कर दलाल के माध्यम से भारत सिमा में आकर बोडायता अपनी पत्नी के साथ रह रहा था, जिसकी एक बेटी भी है।

बांग्लादेशी पीड़ित महिला सुर्पना राय।

भतीजा विपलब राय व अजीत राय भारतीय व्यवस्था को धुमिल करने वाले अब महिला को भी कर रहे प्रताड़ित।

पत्नी को प्रताडित करने वाला विपलब नाम बदल रविदास बनकर रह रहा बोडायता में

अजीत राय का भतीजा विपलब राय जिसका खवासा पंचायत में नाम दर्ज होकर उसके साथ उसकी पत्नी का भी नाम दर्ज है, जो बोड़ायता में विपलब की जगह अपना नाम बदलकर रविदास रख बोड़ायता पंचायत में पंजीयन करवाकर रह रहा है, जो अपनी बांग्लादेशी पत्नी को प्रताड़ित कर बेरहमी से मार-मारकर, काका अजीत राय के सहयोग व संरक्षण में उसे निकाल दिया और पश्चिम बंगाल में दलाल के सुपुर्द कर बांग्लादेश उसकी बेटी के साथ भेज दिया।

उक्त पीड़ित महिला ने एक वीडियो जारी किया जिसमें बताया कि, मैं बांग्लादेश की हु व बांग्लादेश में ही रह रही हूं जो शायद हमारे तंत्र की आंखें खोलने के लिए पर्याप्त होगा कि, स्वयं वह महिला ने माही की गूंज को वीडियो जारी कर बताया कि, मेरा नाम सुर्पना राय है मैं एमपी में झाबुआ जिले के पेटलावद के बोड़ायता में 8 वर्ष रहकर आई हूं, पर मेरा नाम खवासा में भी है, मेरा पति विपलब राय हाथ-पैर बांधकर मुझे मारता था, शराब पीकर मेरी बेटी को भी मारता था, मेरे साथ जबरदस्ती भी करता था, दूसरे की बीबी से चक्कर भी चल रहा था जिसके कारण भी मुझे लोगों के सामने भी मारता था और जानवर की तरह मेरे साथ व्यवहार करता था, अब वह दूसरी महिला के साथ शादी कर रहा है यह सुना है, मेरे पिता बहुत गरीब है बांग्लादेश में रहते हैं, मुझे पश्चिम बंगाल में दलाल के सुपुर्द कर चले गए थे। मैं मेरी बेटी भावना के साथ मेरे पिता के यहां बांग्लादेश में हूं, विपलब मुझे कोई खर्चा भी नहीं दे रहा है जिससे मैं मेरी बेटी की पढ़ाई व परवरिश कैसे करू? सभी दस्तावेज भी विपलब के पास है, के साथ गूंज के माध्यम से न्याय की अपील वीडियो जारी कर की है। विपलब राय उर्फरविदास की पत्नी सुर्पना ने यह स्पष्ट रूप से खुलासा कर दिया कि, वह बांग्लादेशी होकर 8 वर्षों से बोड़ायता में रह रही थी, लेकिन उसका नाम खवासा में भी दर्ज है, वरन वह गरीब परिवार की होकर वर्तमान में उसी के देश बांग्लादेश में अपने पिता के साथ रहकर फर्जी एवं बांग्लादेशी विपलब राय से न्याय की मांग कर रही है। उक्त वीडियो के साथ हमारे तंत्र के सामने यह बात भी स्पष्ट रूप से खुलासा करती है कि, बांग्लादेशी किस तरह से भारत में आकर भारत की मूल व्यवस्था को धूमिल कर हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

माही की गूंज अपनी वेबसाइट माही की गूंज डॉट इन पर उक्त वीडियो को जारी किया जाएगा।

काका अजीत राय के इशारो पर भतीजा विपलब पत्नी को करता था प्रताडित का लगया आरोप

उक्त खुलासे के बाद भी हमारा तंत्र कुछ नहीं करता है तो तय है यही माना जाएगा कि, अपनी पहचान छुपाकर भारत में आ रहे विदेशी को पनाह खुले रूप से हमारा तंत्र ही दे रहा है। वीडियो जारी करने के बाद जब मोबाइल से गूंज की बांग्लादेश में रह रही सुर्पना से सीधी बात हुई तो बताया, मैं बहुत परेशान हूं विपलब राय ही अपना नाम रविदास रख बोडायता में रह रहा है, खवासा में रह रहे अजीत राय का मेरे पति विपलब को पूरा संरक्षण है और उसी के इशारे पर विपलब मेरे साथ मारकुट करता था और अजीत राय के साथ विपलब ने पश्चिम बंगाल मे सोबुज नाम के दलाल जिसका मोबाइल नंबर 008801731930042 है के सुपुर्द कर चोर रास्ते से मुझे बांग्लादेश भेज दिया था। सुर्पना ने स्पष्ट रूप से कहा कि, मुझे प्रताड़ित करने में मेरे पति के साथ अजीत राय बराबर सरिक है।

विवादित बयान को लेकर पूर्व केन्द्रीय मंत्री, कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया पर दर्ज कराई एफआईआर

माही की गूंज, झाबुआ

पुर्व केन्द्रीय मंत्री व कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया के विवादित बयान की झाबुआ कोतवाली में हुई शिकायत।

मंगलवार को कांग्रेस के धरना प्रदर्शन के दौरान झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया द्वारा अपने संबोधन मे कोरोना महामारी से मृतको की संख्या पर दिये गए बयान को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए विवादित बयान दिये गए।

ओमप्रकाश शर्मा अधिवक्ता के द्वारा झाबुआ थाने मे आवेदन देकर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। जिसमे शर्मा द्वारा बताया गया कि, झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया के द्वारा धरना प्रदर्शन के समय 30 जून को एक बयान में कहा गया कि, विश्व व्यापी कोरोना महामारी के चलते भारत मे करीब ढाई लाख लोगो की कोरोना महामारी से मृत्यु हुई है। म.प्र. में करीब 40-50 हजार लोगो की मृत्यु हुई हे। यही नही डब्लुएचओ संस्था पुरे देश पर मॉनिटरिंग रखे हुए है। यदि एक भी दूर्घटना कोरोना से होती है तो पुरे भारत मे किसी भी राज्य में एक्शन प्लान मे लेकर इसमे एक-एक का रिकार्ड रखा जाता है, और उसके बाद इसकी जानकारी दी जाती है, कितने लोगो की मृत्यु हुई है एवं कितने लोग इस महामारी से संक्रमित हुए है। परन्तु झाबुआ विधायक भूरिया झाबुआ की जनता को अनपढ गवार समझते है ओर कुछ भी भाषण देकर लोगो को भडका रहे है। शर्मा ने कहा कि, कोई भी बिना तथ्यो की जानकारी नही दी जा सकती है और ऐसा भ्रम नही फैलाया जा सकता है। जिससे लोगो में अफरा-तफरी मच जाए। इसके लिये मेरे द्वारा झाबुआ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि, महामारी अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की जाए जिससे ये पूनरावृत्ति ना हो। अनावश्यक कोई ऐसे बयान बाजी ना हो जिससे देश प्रदेश की छवी, खराब ना हो। भारत के नागरिक है फिर चाहे वह विधायक हो या फिर सांसद हो किसी के खिलाफयदि उन्होने कोई ऐसा कृत्य किया है तो उनके खिलाफअपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिये ओर यह मेरा अधिकार है इस नाते मेरे द्वारा झाबुआ थाने मे रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है।

कांग्रेस के कदावर नेता कांतीलाल भूरिया के विरूद्ध शर्मा ने करवाई थाने मे रिपोर्ट दर्ज।

शिवराज चौहान के मंत्रिमंडल में शामिल हुए 28 मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के 12 नेता मंत्री बने

भोपाल। मध्य प्रदेश में भाजपा की शिवराज सरकार का गुरुवार को मंत्रिमंडल विस्तार किया गया, जिसमें गुरुवार को राजभवन में करीब 28 विधायक मंत्री पद की शपथ ली। इसमें शिवराज सिंह के पिछले मंत्रिमंडल में सीनियर विधायक व पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव भूपेंद्र सिंह यशोधरा, राजे विजय शाह ने मंत्री पद की शपथ ली। गुरुवार को 28 मंत्रियों के शपथ ग्रहण के साथ अब शिवराज के मंत्रिमंडल में 34 मंत्री हो गए है। गुरुवार को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के 12 नेता मंत्री बने हैं। इनमें सिंधिया खेमे के महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रभु राम चौधरी, प्रद्युमन सिंह तोमर, इमरती देवी, राजवर्धन सिंह, बृजेंद्र सिंह यादव, सुरेश धाकड़, गिर्राज दंडोतिया, ओ पी एस भदौरिया, हरदीप सिंह डंग, बिसाहूलाल सिंह और एंदल सिंह कसाना को मंत्री बनाया गया है।

मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायक
1.गोपाल भार्गव (कैबिनेट)
2. विजय शाह (कैबिनेट)
3.जगदीश देवड़ा (कैबिनेट)
4. प्रेम सिंह पटेल (कैबिनेट)
5. यशोधरा राजे (कैबिनेट)
6.भूपेन्द्र सिंह (कैबिनेट)
7.अरविंद सिंह भदोरिया (कैबिनेट)
8. एदल सिंह कसाना (कैबिनेट)
9.ओपी सकलेचा (कैबिनेट मंत्री)
10-बृजेंद्र प्रताप सिंह (राज्य मंत्री)
11.विश्वास सारंग (कैबिनेट मंत्री)
12.ऊषा ठाकुर (राज्य मंत्री)
13.मोहन यादव (कैबिनेट मंत्री)
14.भारतसिंह कुशवाह (राज्य मंत्री)
15.इंदर सिंह परमार (राज्य मंत्री)
16.रामखिलावन पटेल (राज्य मंत्री)
17.हरदीप सिंह डांग (राज्य मंत्री)
18.रामकिशोर कांवरे (राज्य मंत्री)
19.राज्यावर्धन दत्तीगांव (राज्य मंत्री)
20.प्रभुराम चौधरी (कैबिनेट)
21.इमरती देवी (कैबिनेट)
22.प्रद्युमन सिंह तोमर (कैबिनेट)
23.महेंद्र सिसोदिया (कैबिनेट)
24..बृजेन्द्र यादव (राज्य मंत्री)
25.सुरेश धाकड़ (राज्य मंत्री)
26. ओपी भदौरिया (राज्य मंत्री)
27.बिसाहू लाल सिंह (कैबिनेट)
28. गिर्राज दंडोतिया

अब दीपावली और छठ तक मिलेगा मुफ्त अनाज - पीएम मोदी

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना लॉकडाउन के बाद से लगातार देश को संबोधित कर रहे हैं। एकबार फिर उनका राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के दौरान देश के 80 करोड़ लोगों को नवंबर महीने तक मुफ्त अनाज देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मैं आप सब से प्रार्थना करता हूं, आपके लिए भी प्रार्थना करता हूं, आपसे आग्रह भी करता हूं, आप सभी स्वस्थ रहिए, दो गज की दूरी का पालन करते रहिए, गमछा, फेस कवर, मास्क ये हमेशा उपयोग कीजिये, कोई लापरवाही मत बरतिए।

पीएम मोदी ने कहा कि अब पूरे भारत के लिए एक राशन-कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है। यानि एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा, जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गाँव छोड़कर के कहीं और जाते हैं। आज गरीब को, जरूरतमंद को, सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय प्रमुख रूप से दो वर्गों को जाता है। पहला- हमारे देश के मेहनती किसान, हमारे अन्नदाता। दूसरा- हमारे देश के ईमानदार टैक्सपेयर। सरकार द्वारा इन पांच महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा भाई बहनों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त दिया जाएगा। साथ ही हर परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। इस योजना के विस्तार में 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे यहां वर्षा ऋतु के दौरान और उसके बाद मुख्य तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है। अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है। जुलाई से धीरे-धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है। त्योहारों का ये समय, जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्चे भी बढ़ाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों के लिए पौने दो लाख करोड़ रुपये का पैकेज दिया गया। बीते 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31 हजार करोड़ रुपए जमा करवाए गए। 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18 हजार करोड़ रुपए जमा हुए है। मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। हमारे यहां वर्षा के दौरान कृषि के क्षेत्र में ही ज्यादा काम होता है। जुलाई से धीरे-धीरे त्यौहार का मौसम शुरू होने लगता है। कोरोना से लड़ते हुए लोगों को तीन महीने का राशन मुफ्त दिया गया। प्रत्येक परिवार को हर महीने एक किलो दाल भी मुफ्त दी गई। अमेरिकी की कुल जनसंख्या से तीन गुना अधिक लोगों को हमारी सरकार ने मुफ्ता अनाज दिया है।

लॉकडाउन होते ही सरकार पौने दो लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज लेकर आई। लॉकडाउन के दौरान देश की सर्वोच्च प्राथमिकता रही कि ऐसी स्थिति न आए कि किसी गरीब के घर में चूल्हा न जले। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हों, सिविल सोसायटी के लोग हों, सभी ने पूरा प्रयास किया कि इतने बड़े देश में हमारा कोई गरीब भाई-बहन भूखा न सोए। पहले हम मास्क को लेकर, दो गज की दूरी को लेकर, 20 सेकेंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे। अब सरकारों को, स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, देश के नागरिकों को, फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। लॉकडाउन के दौरान लोगों ने गंभीरता से नियमों का पालन किया था। लेकिन अनलॉक में आते ही लापरवाही बढ़ती जा रही है। लोगों को सतर्कता बरतनी होगी। अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है। लेकिन जब से देश में अन लॉक वन हुआ है तब से लापरवाही कुछ बढ़ती जा रही है। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफलड़ते-लड़ते अब हम अनलॉक-2 में प्रवेश कर रहे हैं। हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं, जब सर्दी, जुखाम, बुखार जैसी बीमारी होती है। मेरी सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि अपना ध्यान रखिए।

खवासा में कार्य हेतु
ऑपरेटर की आवश्यकता

हिन्दी व इंगलिश टाईपिंग
आनलाईन सभी कार्य
फोटोशॉप व अन्य एडिटिंग
साफ्टवेयर का अनुभव रखने
वाले इच्छुक व्यक्ति सर्म्पक करे
नोटः-योग्यता अनुसार सेलेरी दि जायगी
पताः-माही की गूंज कार्यालय, ओम श्री सॉई ट्रेडर्स खवासा
मों.नं. 9589882798

अंधेर नगरी चौपट राजा उर्फ जनपद पंचायत पेटलावद, भ्रष्टों के आगे नतमस्तक जनपत सीईओ एनएस चौहान

ग्रामीणों की शिकायत पर हटाए गए रोजगार सहायक को दस दिन में वापस दिया चार्ज

माही की गूंज, पेटलावद

पेटलावद विकास खण्ड गले-गले तक भ्रष्टाचार में डूबी, ग्राम पंचायतों का केंद्र बिंदु जनपत पंचायत पेटलावद ओर उसके सीईओ एनएस चौहान साबित हो रहे हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा की तरह सीईओ चौहान भी अपनी नोकरी के कर्तव्य को लजाकर अपनी मातृभूमि को नीचा दिखा रहे हैं। ग्राम पंचायतों के माध्यम से हो रहे जनहितैषी कार्य और शासकीय योजनाओं को धरातल पर लाने का कार्य चल रहा है, जब इन कार्यो में लापरवाही ओर भ्रष्टाचार होता हैं तो आमजन सबसे पहले जनपत पंचायत के सीईओ से गुहार लगाते हैं, लेकिन चौहान अब धीरे-धीरे इन भ्रष्टो का राजा साबित हो रहा है। गत दिनों मनरेगा के कार्यो में जेसीबी चलने से लेकर कागजो पर हुए कार्यो के कई समाचार प्रकाशित हुए, लेकिन कार्यवाही के नाम पर सब शून्य कर दिया गया, खुलेआम हुए भ्रष्टाचार को सीईओ चौहान ने जांच के नाम पर दबा दिया, जब साहब से पूछा जाता है कि आपने क्या कार्यवाही की तो कहा जाता हैं कि हम कार्यवाही नही कर सकते हमारा काम केवल जिले के अधिकारियों को प्रतिवेदन भेजने का है जो हम भेज देते हैं। किसी पंचायत पर उठाकर प्रतिवेदन के बारे में जब सवाल किया जाता हैं तो केवल एक ही जबाब मिलता है, हमको जो लिखकर भेजना था भेज दिया अब जिले वाले जाने।

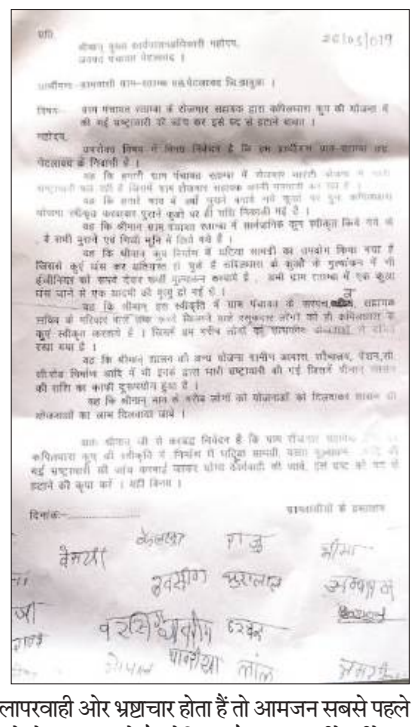

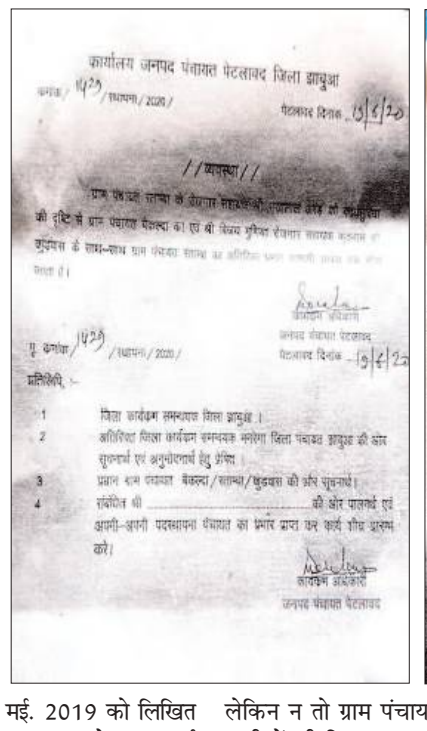

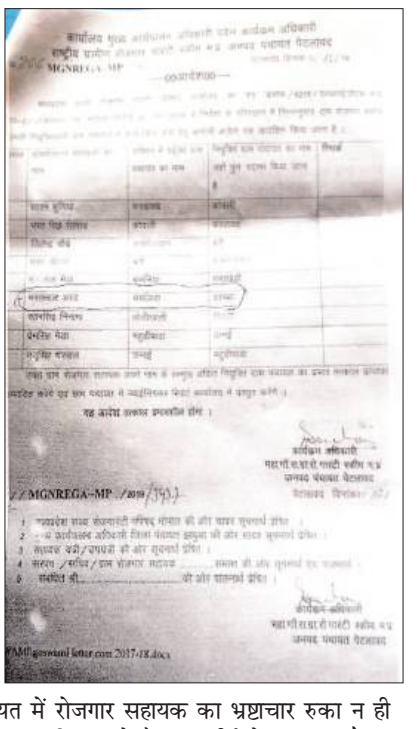

ताजा मामला ग्राम पंचायत रतम्बा का है जहाँ से पूरी पंचायत के ग्रामीण रोजगार सहायक भरतलाल अरड के खिलाफ 25 मई. 2019 को लिखित जनपत सीईओ ओर 22.जनवरी .2019 और 25 जुन .2019 को जनसुनवाई में जिला कलेक्टर को की गई, जिसमें बताया गया कि, रोजगार सहायक मे गाँव के बने हुए कुओ पर नवीन कपिल धारा स्वीकृत कर फर्जी रूप से राशि निकली गई और उपयंत्री द्वारा फर्जी मूल्यांकन किया गया, ग्राम पंचायत के अंतर्गत होने वाले ग्रामीण आवास, शौचालय, सीसी रोड में भ्रष्टाचार, फर्जी हाजरी और फर्जी बिल लगाकर पैसे निकाल कर भ्रष्टाचार करने की गंभीर शिकायत की गई, ग्रामीणों की शिकायत के बाद रोजगार सहायक भरतलाल अरड को हटा दिया गया, लेकिन पेसो के दम पर जनपत के अधिकारियों से सेटिंग कर दिनांक 05 दिसम्बर 2019 को जारी कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा जनपत पंचायत पेटलावद के आदेश से वापस रतम्बा पंचायत में पहुँच गया, लेकिन न तो ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक का भ्रष्टाचार रुका न ही ग्रामीणों की शिकायत लगातार शिकायतो के बाद सीईओ नानूराम चौहान द्वारा एक आदेश क्रमांक/1429/स्थापना/2020/ पेटलावद दिनांक 19 जून 2019 को व्यवस्था के नाम पर जारी किया जिसमें रतम्बा से भरतलाल अरड बेकलदा पंचायत और कुड़वास के रोजगार सहायक विजय मुनिया को ग्राम पंचायत रतम्बा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, रोजगार सहायक विजय मुनिया के आदेश अनुसार 24.जून.2019 को रतम्बा का प्रभार ले लिया लेकिन पैसे के दम पर एक बार फिर रोजगार सहायक भरतलाल अरड को केवल 10 दिन के वनवास के बाद वापस रतम्बा भेज दिया गया, चुकी मामले में कोई आदेश अब तक जनपत सीईओ ने सार्वजनिक नही किया, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार भरतलाल अरड को पुनः रतम्बा भेज कर विजय मुनिया से रतम्ब का अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया गया, जिसकी पुष्टि के लिए रतम्बा के सचिव मोहन मावी से जानकारी मांगी तो उसने बताया कि, मेरे पास कोई लिखित जानकारी नही है लेकिन अतिरिक्त प्रभार वाले रोजगार सहायक विजय मुनिया से बात की तो उसने बताया कि, मुझे सीईओ साहब ने मौखिक आदेश देकर ग्राम पंचायत रतम्बा से कार्य मुक्त कर दिया है। जनपत में चल रही चर्चाओं से पता लगा है कि जनपत पंचायत पेटलावद में रोजगार सहायको की बार-बार पंचायत से अदला-बदली कर वापस अपनी मूल पंचायत में वापस भेजने के लिए 50 हजार से एक लाख तक कि वसूली की जा रही हैं, जिसमे जनपद से जिला जनपद की पूरी चौनल शामिल है क्योकि 05.12.2019 जारी आदेश में भरतलाल अरड के साथ-साथ लगभग 09 रोजगार सहायको की पंचायत बदली गई थी, जो या तो अपनी मूल पंचायत पहुचाया गया या फिर जिन पंचायत में पदस्थ थे वहाँ से हटाकर दुसरी पंचायतों में भेजा गया, लेकिन वर्तमान में अधिकांश हटाए गए सहायक सचिव उसी पंचायत में पदस्थ हैं जहाँ से हटाए गए है, पूरे खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी जनपत सीईओ नानूराम चौहान हैं जो भ्रष्ट उपयंत्री, सरपंच-सचिव और रोजगार सहायकों के खुले भ्रष्टाचार में पूरा सहयोग कर जांच के नाम पर बचाने के नाम पर लाखों अंदर कर रहा है, इसका सीधा सा प्रमाण यही है कि, अब तक किसी भी भ्रष्ट उपयंत्री और सचिव, रोजगार सहायक पर कोई बड़ी कार्यवाही नही हुई हैं उल्टा उसी पंचायत में रहकर खुले भ्रष्टाचार करना जारी है ।

ग्रामीण फिर पहुँचे झाबुआ कलेक्टर के पास

भ्रष्ट रोजगार सहायक को हटाकर वापस रतम्बा पदस्थ करने के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश भर गया और बड़ी संख्या में ग्रामीणो ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को फिर से शिकायत की, मामले में पूरे गाँव के विरोध के बाद भ्रष्टाचार की जांचकर भ्रष्ट रोजगार सहायक को निलंबित करने की बजाए केवल पंचायत से हटाया गया वो भी लेन-देन कर आदेश निरस्त कर दिया गया, वही मामले को लेकर भाजपा संगठन में भी नाराजगी है। मामला रायपुरिया मंडल में होने के बाद भी अन्य मंडल से अध्यक्ष अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर ग्रामीणों की शिकायत को अंगूठा बताकर अधिकारियों और भष्टो के बीच सेटिंग करवाकर मामले को लेन-देन कर निपटवा रहा हैं, रायपुरिया मंडल अध्यक्ष ने कहा है कि, मामले की शिकायत ऊपर संगठन से करूंगा।

शासकीय कर्मचारी नाजिर का बेटा बना सप्लायर यह है कोरोना का असर

कोरोना महामारी को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय मे पदस्थ नाजिर के माध्यम से की गई खरीदी मे लाखो का भ्रष्टाचार-जांच की मांग उठी

माही की गूंज झाबुआ।

कोरोना महामारी को लेकर देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कई देशवासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रधानमंत्री राहत कोष में राशि दान मे दी, तो झाबुआ जिले में भी कई लोगों ने तेल ,शक्कर ,आटा आदि के पैकेट बनाकर गरीब जनों को वितरित किए। कोरोना की रोकथाम हेतु या सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन समिति के माध्यम से सामग्री टेंडर पदति के माध्यम से खरीदी की। जिसमें गुलाबी बिल्डिंग में कार्यरत नाजिर के पुत्र अफरोज कुरैशी की फर्म बाबा एंटरप्राइजेज द्वारा टेंडर में सामग्री के बाजार मूल्य से कई ज्यादा अधिक दरें दी गई हैं। आपदा के इस समय में इस फर्म द्वारा आर्थिक हितों को सर्वोपरि मानते हुए मानवता की एक मिसाल पेश की और बाजार मूल्य से कई अधिक दरो मे सप्लाय की। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसी के साथ ही उत्कृष्ट विद्यालय मे भी 12 वी की परीक्षा के पूर्व खरीदी गई सामग्रीया मे भी बडा गोलमाल किया गया है। जिसमें खुद आयशा कुरैशी द्वारा इन सामग्रीयो का क्रय किया गया है। वही बाजार मुल्य से अधिक के भाव में बच्चो के लिये सेनेटाईजर खरीदे गए है। अगर इन सभी पहलुओ की गंभीरता से जांच की जाये तो जरूर ही एक बडे गोलमाल का खुलासा हो पायेगा।

यदि हम सामग्री के मूल्य की बात करें तो झाबुआ बाजार में इन सामग्रियों के मूल्य की जांच पड़ताल की तो पता चला की जो दरे, बाबा इंटरप्राइजेज द्वारा दी है वह बाजार मूल्य से करीब 25 रूपए से 200 रूपए तक अधिक है। विपदा की इस घड़ी में इस फर्म और फर्म संचालक द्वारा इस तरह की अधिक दरे प्रेषित करना कहां तक न्यायोचित हैं। जबकि एक छोटे से गूगल क्लिक पर इन

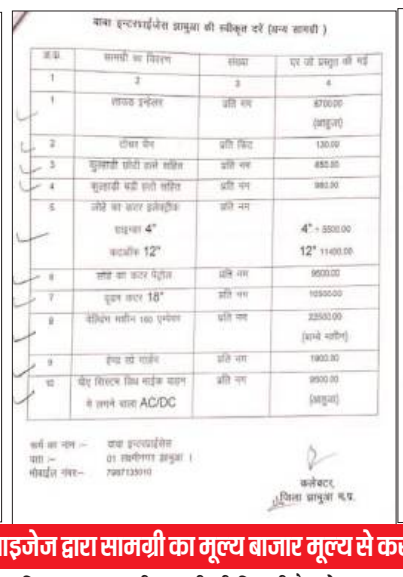

नाजिर के पुत्र की फर्म बाबा इंटरप्राइजेज द्वारा सामग्री का मूल्य बाजार मूल्य से करीब 25 से 200 रूपए तक अधिक

सामग्रियों की सारी दरें और स्पेसिफिकेशन हमें तत्काल मिल जाता है, उसके बाद भी अत्यधिक दरों में खरीदी करना जनता के साथ धोखा करने के बराबर है। यदि हम सामग्री खरीदी की बात करें और दरों की बात करें तो ऊपर दी गई तालुका से स्पष्ट है कि बाजार मूल्य से दो से 3 गुना अधिक दरों पर खरीदी की गई, गुलाबी बिल्डिंग अर्थात जिला कलेक्टेड मे पदस्थ नाजिर एजाज कुरेशी द्वारा षडयंत्र पूर्वक आपसी सांठ-गांठ करके अपने पुत्र की फर्म एवं दो उसकी सहयोगी फर्म के नाम से टेंडर बुलवा लिए जबकि टेंडर की कहानी भी निराली है, जो वस्तुए खरीदी गई है उनका ही ओपन टेडरिंग होना था, परंतु नाजिर का खेल यहा चला ओर नाजीर ने पांच लाख से नीचे टेंडर सीधे-सीधे अपने लडके ओर उनकी सहयोगी फर्म के बुलवा लिये ओर उन्हे सीध-सीधे आर्डर दे दिये। उक्त टेंडरो के माध्यम से जो आयटम कलेक्टर द्वारा खरीदी गई है नाजिर के माध्यम से बाजार भाव से उन आयटमो के भाव मे जमीन आसमान का अंतर है। वस्तुओ के सप्लायरो द्वारा सप्लाय करने पर इनका भौतिक सत्यापन किन अधिकारीयो ने किया है इसकी भी जांच होना चाहिए। वही जब लाखो की खरीदी की जाना थी तो ओपन ई-टेंडर काल 5 लाख से ज्यादा के क्यो नही बुलाये गये जबकि षडयंत्रपूर्वक इन आयटमो के ई-टेंडर चार लाख या साढे चार लाख क्यो रखे गये। इससे स्पष्ट होता है कि कलेक्ट्रेड मे पदस्थ नाजीर के पुत्र व उनके सहयोगी फर्मो से इनकी सांठ-गांठ हो गई थी ओर इस पर कलेक्टर का भी वृहद हस्त अपने नाजीर को षडयंत्र के रुप मे मिल रहा था, तभी वह इतना बडा दुस्साहस कर रहा है।

भावसार ने मुख्यमंत्री से जांच की मांग

भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पूर्व जिलाध्यक्ष दौलत भावसार ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि आपदा प्रबंध के नाम पर जितनी भी झाबुआ जिला प्रशासन ने खरीदी की है उसकी उच्चस्तरीय जांच कर उन वस्तुओ की गुणवत्ता की जांच करने पर यदि वह गलत पाई जाती है तो उनके खिलाफकार्यवाही की मांग की गई है। साथ ही यह भी जांच की मांग की है कि, बाजार मूल्य से इतनी अधिक दरों पर खरीदी क्यों की गई? क्या मध्य प्रदेश शासन इस और ध्यान देकर जिले में आपदा प्रबंधन के समय सामग्री खरीदी की दरों की कोई जांच करेगा या फिर यह अधिकारी कर्मचारी यूं ही जिले की जनता को भ्रमित करते रहेंगे और अपने निजी हितों को साधते रहेंगे।

बिजली बिलों की समस्याओं को लेकर दिया आवेदन

माही की गूंज, झाबुआ।

विद्युत बिलों की समस्या के निराकरण के लिये व्यापारी संगठन ने सौपा ज्ञापन।

नगर में बढते बिजली बिलो की समस्यसाओ को देखते हुये व्यापारी संगठन के द्वारा बुधवार 01 जून को विद्युत मंडल के एसी श्री वर्मा को ज्ञापन सौपा। जिसमें उनके द्वारा नगर सहित व्यपारियो के घरो एवं प्रतिष्ठानो पर कई हजारो रूपये मे बिजली के बिल थमा दिये गये है। जिसमे बिजली विभाग के द्वारा बताया गया कि उन्हे ऐवरेज बिल दिये गये है। लेकिन वही व्यापरियो के द्वारा यह तक बताया गया कि यदि पिछले तीन से चार महिनो में बिजली के बिल कम आये है तो मई माह के बिजली के बिलो मे ऐवरेज बिल हजारो रूपये मे केसे आ सकते है। इसके लिये व्यापारि संगठन के द्वारा विद्युत विभाग के अधिकारी श्री वर्मा का समस्याओ के निराकरण के लिय ज्ञापन सौपा। वही श्री वर्मा द्वारा यह आश्वासन दिया गया वही उनके द्वारा बताया गया कि 7 जून 2020 मंगलवार को भी जनसमस्यास निवारण शिविर रखा जायेगा जिसमे समस्या का समाधान किया जायेगा।

मौत का केप्सुप...

नियम के विरुद्ध स्टेट हाइवे से गुजर रहे हैं गैस के टैंकर

क्षमता से अधिक वजन ढो नही पा रहे रोड, टोल बचाने के लिए कर रहे रोडो का नाश

माही की गूंज , पेटलावद

जिले के मुख्य रोडो से गुजरने वाले यहाँ इंडियन आयल गैस कम्पनी के टैंकर (केप्सुप) सहित क्षमता से अधिक वजन के वाहनो के मुख्य मार्ग छोड़कर अन्य मार्गो से गुजरने के कारण रोडो का नाश कर रहे हैं और अधिक क्षमता के कारण रोड समय से पहले ही स्वाहा हो जाते हैं। गत दिनों पेटलावद में थांदला-बदनावर मार्ग पर टोल वसूल रही ईगल दिप कंपनी के कर्मचारियों द्वारा बदनावर की ओर से आ रहे है गैस के टैंकरों को रोककर टोल मार्ग से गुजरने के लिए दबाव बनाया गया, ये टैंकर पेटलावद तक टोल कंपनी के अंतर्गत आने वाले लगभग 55 किलोमीटर का रोड उपयोग कर पेटलावद से रायपुरिया होकर अन्तरवलिया होकर टोल बचा कर गुजरात की ओर जाते हैं, शुरू-शूरू में मामला टोल कर्मचारियों द्वारा दादागिरी से टोल वसूलने और टैंकरों के ड्राइवरों के टोल बचाने का लग रहा था, लेकिन मामले की तह तक जाने पर पता लगा कि, इंडियन ऑयल के ये टैंकर अपना रूट छोड़ कर गलत तरीके से गलत रोडो से निकल कर दुसरे रोडो को भारी नुकसान पहुँचा रहे हैं।

तय रूट से निकला जरूरी ट्रान्फोटर बचत के लिए निकालते हैं दूसरे रोडो से

मामले की जानकारी लेने पर पता चला कि, गैस टेंकरो का जाने का रूट तय होता हैं और कंपनी द्वारा ड्राइवरों को मेप दिया जाता है जिसके हिसाब से उनको चलना होता है लेकिन ट्रान्फोटर अपना डीजल ओर खर्च बचाने के लिए मनचाहे रूट से निकल जाते हैं, लेकिन मैप के हिसाब से इन टैंकरों को इस रूट पर आना ही नही है इनका सही रुट उज्जैन-इंदौर होकर झाबुआ से गुजरात होता है, लेकिन ये टैंकर सीधे उज्जैन से बदनावर होकर पेटलावद का टोल बचाकर रायपुरिया से अन्तरवलिया निकलते हैं, टैंकर की क्षमता 40 टन ओर उससे भी अधिक होती है, जबकि पेटलावद से लेकर अन्तरवलिया तक का रोड 30 टन ही पास है और रोज कई टैंकर इन रोडो से टोल बचाने के लिए निकल जाते हैं। टोल कम्पनी ईगल दीप के कर्मचारी इन टेंकरो को टोल रोड से गुजरने के लिए पेटलावद श्रद्धांजलि चोक पर खड़े रहते हैं, साथ ही एक बन्दूकधारी भी खड़ा किया गया हैं जो टोल रोड़ छोड़ कर जाने वाले टेंकरो को टोल रोड पर घूमते हैं। मामले में टोल एडमिन भारत हिरवाने का कहना है

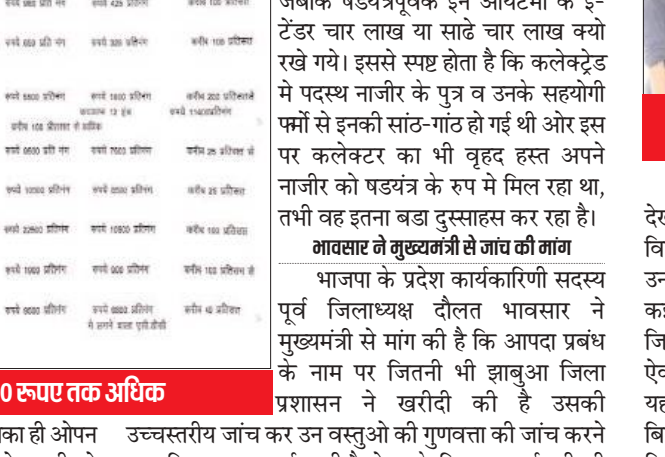

कि, गैस कंपनी टोल रोड से गुजरने वाले गैस टैंकर 55 किलोमीटर का रोड़ का उपयोग कर रहे हैं बाकी टोल बचाने के लिए गलत रुट से निकल रहे हैं हमारे द्वारा टोल के मुख्य अधिकारीयो के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग और आरटीओ अधिकारी को भी कई बार अवगत करा दिया गया लेकिन कोई कार्रवाई नही हुई इसलिए मजबूरन हमको टेंकरो को टोल रोड से जाने का कहा जा रहा है। वही इंडियन गैस उज्जैन के सुरक्षा अधिकारी सुमित आलोक का कहना है कि, हमारे टैंकर तय रुट से ही चलते हैं यदि टैंकर अपना रुट छोड़ कर दूसरे रुट पर 300 मिटर भी निकले तो हमको पता लग जाता हैं और ऐसा करने पर टैंकर वालो पर हम 5 हजार रूपए की पेनेल्टी करते हैं, टोल वालो को कोई अधिकार नही की वो टेंकरो को जबरन दूसरे रोड से निकलने से रोके ये काम टोल कम्पनी के कर्मचारियों का नही है, दो साल के लिए रायपुरिया वाला ही रोड मैप में निर्धारित है। टेंकर ड्राइवरों के पास मिले मैप में ऐसा कोई रुट नही दर्शाया गया ओर अगल-अलग टेंकरो से अलग-अलग रोड के मैप मिले है।

यातायात विभाग, लोक निर्माण विभाग और पुलिस विभाग निष्क्रिय

न केवल क्षमता से अधिक भारी वाहन टोल रोड बल्कि अन्य रोडो से भी गुजर रहे हैं जिससे सड़के समय से पहले ही खत्म हो रही है कई बार शिकायतो के बाद भी कार्यवाही करने वाला यातायात विभाग, लोक निर्माण विभाग और पुलिस विभाग अपनी ओर से कोई कार्यवाही नही करता जिससे लगातार इन रोडो पर भारी वाहनों का रस रहता है और आये दिन दुर्घटना ओर ट्रैफिक जाम की समस्या होती हैं। रायपुरिया से अन्तरवलिया रोड़ जो कि 30 टन पास है से टोल बचाने के लिए इस रूट का सहारा लेते है, अधिक वजनी वाहनों के गुजरने से रायपुरिया अन्तरवलिया रोड के दो से तीन बड़े पुल भी धराशाही हो चुके है और कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त भी हो चुके है लेकिन आज तक इन क्षमता से अधिक वजन वाले वाहनों पर कोई बड़ी कार्रवाई नही हुई है।

टोल कंपनी नही बना सकती दबाव

जिस तरह से टोल के कर्मचारियों द्वारा वाहनों को रोक कर टोल रोड से जाने के लिए दबाव बनाया जाता है या दादागिरी की जाती हैं उसका कोई अधिकार टोल कंपनी के पास नही है, यदि कुछ गलत हो रहा है तो टोल कम्पनी जबाबदार विभाग को लिख कर कार्यवाही की मांग कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में ऐसे मामले सामने आए जब टोल कर्मचारियों द्वारा टेंकरो के साथ-साथ दूसरे वाहनों को रात में टोल रोड से गुजरने के लिए वाहनों को रोकते हुवे नजर आए।

पुराना रेकॉर्ड गायब कर गरीब की भूमि हतियाना चाहता हैं नगर परिषद का मोटा भाई

भूमि पर पहले कार्यकाल में ही नजर डोल गई थी, अब दे रहा है इरादों को अंजाम

माही की गूंज, पेटलावद

पेटलावद एसबीआई के पास लगभग 70 सालों से निवास कर रहे गुर्जर परिवार के साथ छल-बल से उनके सर की एक मात्र छत छीनने का प्रयास करने के पीछे नगर परिषद अध्यक्ष मनोहरलाल भटेवरा (मोटा भाई) की गहरी साजिश का खुलासा हुआ है। गूंज के हाथ उक्त भूमि को लेकर ऐसे पुराने दस्तावेज लगे हैं जिसको देखने के बाद पता चला कि, नगर परिषद के वर्तमान अध्यक्ष मोटा भाई इस भूमि को आज से नही 90 के दशक मे पहले कार्यकाल जब मनोहर भटेवरा अध्यक्ष बने थे तब से ही खराब है। मोटा भाई ने अपने पहले कार्यकाल में किये काले कारनामो के रिकॉर्ड गायब करने में गुर्जर परिवार का भी रेकॉर्ड गायब कर दिया और भूमि पर गुर्जर परिवार का अतिक्रमण बताकर 1995 में राजस्व न्यायालय से रेकॉर्ड के अभाव में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण सिद्ध कर मकान तुड़वा दिया।

पुराना रिकार्ड कह रहा अपनी कहानी

कहते हैं सच तो सच होता हैं, कितना भी छुपा लो एक न एक दिन सामने आ ही जाता है, गूंज के हाथ लगे पुराने दस्तावेजो से आज ये खुलासा करेगे की उक्त भूमि पर न केवल गुर्जर परिवार काबिज हैं, बल्कि भूमि भी गुर्जर परिवार की ही है। नगर पालिका रेकार्ड में 80 के दशक में उक्त सम्पत्ति बकायदा राधाकिशन पिता देवीलाल गुर्जर के नाम से दर्ज थी वर्ष 1982 ओर 1985 में राधाकिशन द्वारा भूभाट (भवन टेक्स) भरा गया था, जिसकी रसीद भी मौजूद हैं। 23 मई 1982 को तत्कालीन नगर परिषद ने 92 रूपए 50 पैसे की रसीद जो कि पुराने समय मे कई वर्षों का भूभाट टेक्स था ओर दिनांक 25 जनवरी 1985 को 12 रूपए 50 पैसे नगर पालिका में भूभाट टेक्स के रूप में जमा गुर्जर परिवार द्वारा किये गए। चुकी भूमि राधाकिशन गुर्जर के परिवार की थी, अपनी रोजी-रोटी की जुगाड़ के लिए अपनी भूमि पर साइकिल रिपेरिंग का कार्य करने के गुमटी लगाने की अनापत्ति प्रमाण-पत्र वर्ष 1987 में तत्कालीन नगर परिषद अध्यक्ष बीएल जाजपर ने दिनांक 06 अप्रैल 1987 को दी गई, लेकिन 1990 के बाद नगर परिषद में मनोहर भटेवरा के अध्यक्ष बनने के बाद पुराना रेकॉर्ड गायब कर दिया गया। तहसील न्यायालय में अतिक्रमण के मामले में गुर्जर परिवार द्वारा दस्तावेज

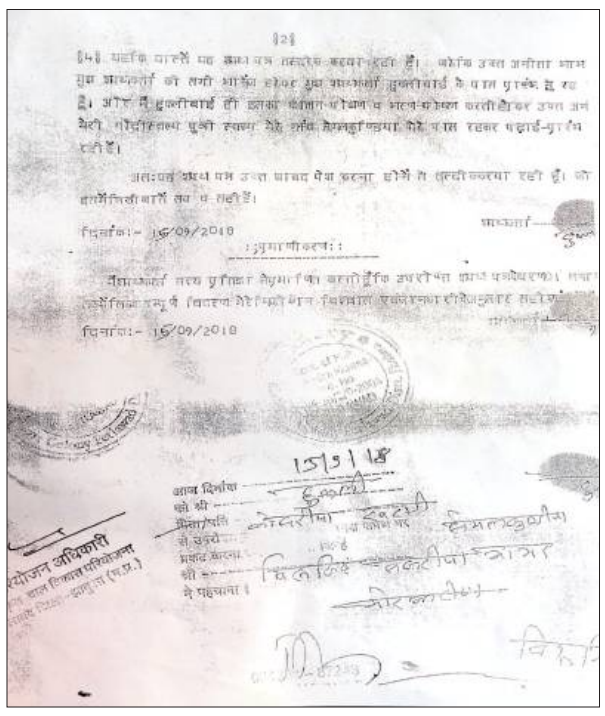

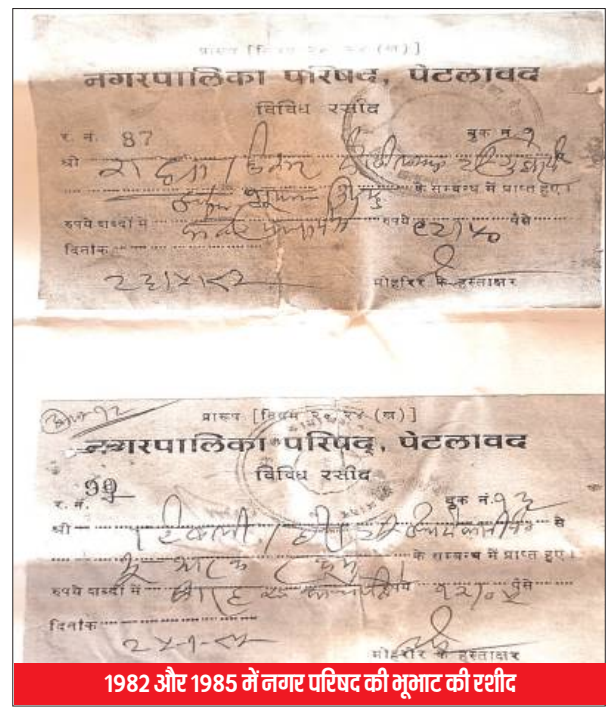

1982 और 1985 में नगर परिषद की भूभाट की रशीद

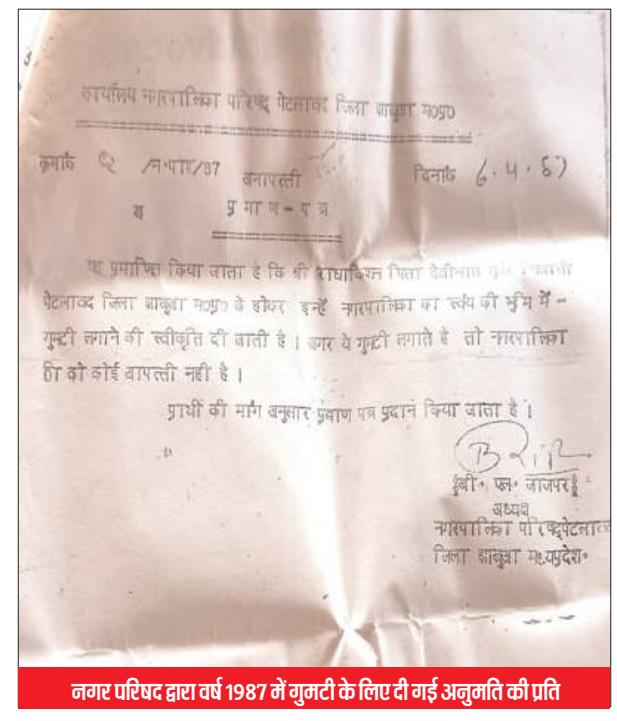
नगर परिषद द्वारा वर्ष 1987 में गुमटी के लिए दी गई अनुमति की प्रति

पेश किए गए, लेकिन गुर्जर परिवार को इस भूमि से हटाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से सारे दस्तावेजों को गायब कर दिया गया और अतिक्रमण सिद्ध कर मकान तोड़ दिया गया।

न्यायालय में हुआ समझौता, दिया गया पट्टा

मामले में तहसील न्यायालय में गुर्जर परिवार के खिलाफहुए निर्णय के बाद प्रशासनिक अमले ने तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी डीके गुप्ता द्वारा अतिक्रमण के नाम पूरे परिवार को सड़क पर फेंक कर घर का सारा सामान जप्त कर लिया था। मामले में राधाकिशन के परिवार ने पेटलावद ओर झाबुआ न्यायालय में अधिकारियों पर गलत तरीके से अतिक्रमण हटाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने और 20 लाख की क्षतिपूर्ति का दावा लगाया जिसमे दोनों पक्षो में समझौता हुआ और समझौते के हिसाब से राधाकिशन के परिवार को उक्त भूमि पर राजीव गांधी आश्रय योजना में पट्टा देना तय हुआ। समझौते के मुताबिक पट्टे के लिए तहसील न्यायालय से विज्ञप्ति 10 अप्रैल 2003 को एक हजार फीट की निकाली गई। वही समझौता अनुसार पट्टे के रूप में न्याय मिलने पर गुर्जर परिवार ने न्यायालय की तारीको पर जाना बंद कर दिया और मामला न्यायालय मे खारिज हो गया। अतिक्रमण हटाने से पहले से आज तक गुर्जर परिवार इसी भूमि पर रह रहा है, कई बार नगर परिषद में गुहार लगाने के बाद भी नामान्तर नही किया गया और लाखों की रिश्वत नामान्तर के लिए मांगी गई, जिसका वहन कर पाना परिवार के लिए संभव नही था, इसलिए न्यायालय के भरोसे आज तक नगर परिषद में नामान्तर नही करवाया। आगे और नए दस्तावेजो के साथ गूंज में पूरे मामले की

जल जंगल जमीन को लेकर जनजाति विकास मंच की कार्यशाला संपन्न

माही की गूंज, थांदला

अंचल के ख्याति प्राप्त देवस्थान श्री स्वयंभू माता मंदिर देवीगढ़ पर जनजाति विकास मंच की एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई।

इस अवसर पर कार्यशाला को अखिल भारतीय जनजाति हित रक्षा मंच के गिरीश कुबेर के मंचासीन मिट्ठू सिंह मुनिया पूर्व वन समिति जामदा के अध्यक्ष सत्तू डामोर ग्राम कोटा के सरपंच कल्लाजी भगत, वैभव सुरंगे, रूपसिंह नागर, नरेंद्र जिला प्रचारक झाबुआ , विजेंद्र निगवाल अवधेश प्रताप, रमेश मुनिया द्वारा विभिन्न सत्रों में जल जंगल जमीन संरक्षण हेतु ग्रामीणों में जागरूकता लाने हेतु संबोधित किया।

कार्यशाला में चयनित कूल 18 गांव में ग्राम समिति वन समिति के माध्यम से गांव का सर्वांगीण विकास किस प्रकार से होना चाहिए तथा जल जंगल जमीन को लेकर हमारे जनजातीय बंधु कितने सक्रिय हैं कितने जागरूक हैं इन तमाम मुद्दों पर सम्मानीय अधिकारियों द्वारा चर्चा की गई बैठक की संपूर्ण भूमिका जनजाति विकास मंच विभागीय संगठन मंत्री कैलाश अमलियार द्वारा रखी गई बैठक में संपूर्ण गांव वालों ने अपने गांव का जंगल फॉरेस्ट विभाग के अधीन है जिसे जंगल की परिसीमन द्वारा उन्हें गांव वालों द्वारा संचालित किया जाना यह भी तय किया इस हेतु एसडीएम एवं कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत कर तमाम मांगों को रखने व उन्हें सुचारू रूप से चरणबद्ध तरीके से चलाने का निर्णय लिया गया, इस अवसर पर श्रमेश मुनिया, शांतु बारिया, श्लालचंद देवल, मोहन सिंगार, यशवंत बामनिया, सहित बड़ी संख्या में जनजाति विकास मंच के कार्यकर्ता उपस्थित थे।

कार्यक्रम का संचालन जनजाति विकास मंच के संजय भाबर ने किया तथा आभार गौर सिंह कटारा ने माना ।

कांग्रेस कमेटी ने मनाया काला दिवस - राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

माही की गूंज, थांदला।

मंगलवार को भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे हो गए है। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के आहवान पर मंगलवार का दिन काला दिवस के रूप में मनाया गया। सभी कांग्रेसजन एकत्रित हुए, अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर मध्यप्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और थांदला तहसीलार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन का वाचन विधानसभा अध्यक्ष युवा नेता राजेश गेंदाल डामोर ने किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक वीरसिंह भूरिया, नगर परिषद अध्यक्ष मनीष बघेल, चौनसिंग डामोर, दिलीप डामोर, गुलाम कादर खान, श्रीमंत अरोरा, रालु वसुनिया एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अनेक पदाधीकारी वरिष्ठ नेता आदि उपस्थित थे।

कांग्रेस राज में रखी आंगनवाड़ी भर्ती की नींव को भाजपा सरकार ने सींचा भाग-3

आवेदनकर्ता ने दी पिता की आईडी, राशनकार्ड और मामी का झूठा शपथ-पत्र

माही की गूंज, पेटलावद, राकेश गेहलोत

पेटलावद विकास खण्ड में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ की फर्जी भर्ती का मामला सामने आने के बाद, विकास खंड में महिला बाल विकास परियोजना कार्यालय से ऐसी ओर भी फर्जी नियुक्ति के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमे पहले पात्र बताई गई महिला को हटाकर, दूसरी महिला को सहायिका ओर कार्यकर्ता दोनों पदों पर नियुक्ति होने पर एक पद से इस्तीफा देने के बाद दूसरे नंबर की महिला को छोड़कर अन्य महिला की नियुक्ति कर दी गई हैं। पूरा खेल पेसो और राजनीति का है, जिसके प्रभाव से पहले पात्र महिला के खिलाफअपील की जाती है और फिर पैसे और राजनीतिक दबाव के दम पर मनचाही महिला की नियुक्ति कर दी जाती है। पैसे के मोह में अंधे अधिकारी वैध कागजी कार्यवाही को ताक में रखकर फर्जी नियुक्ति कर देते हैं। ऐसे ज्यादातर मामले एसडीएम कोर्ट और कलेक्टर कोर्ट तक पहुँचते भी है लेकिन पेट घुटने की तरफमुड़ने वाली कहावत की तर्ज पर मामले में फर्जीवाड़ा देखने के बाद भी आवेदक की अपील को डस्टबीन में डाल दिया जाता है और फर्जी नियुक्ति करने वालो पर किसी प्रकार की कार्यवाही नही की जाती हैं। ग्राम पंचायत मोहनकोट के सेमलकुण्डिया गाँव के मैम्बर फलिये में हुई आंगनवाडी कार्यकर्ता की नियुक्ति में हुए फर्जीवाड़े का परत दर परत हो रहे खुलासे से साफहै कि किस तरह महिला बाल विकास विभाग में फर्जी नियुक्तियो का बड़ा खेल चल रहा है। अपनी नियुक्ति के लिए फर्जी दस्तावेज देने वाली अनिता पिता वरसिंह भाबर द्वारा नियुक्ति हेतु पेश आवेदन के साथ कुछ दस्तावेजो का खुलासा हो चुका है लेकिन सूचना के अधिकार में निकाली गई जानकारी में अनिता भाबर ने एक शपथ-पत्र पेश किया, जिसमे बताया की वह मोरझारिया की नही सेमलकुण्डिया की निवासी है। महिला बाल विकास की परियोजना अधिकारी के समक्ष अनिता ने पहले तो अपने आवेदन के साथ जरूरी गरीबी रेखा का राशनकार्ड अपने नानाजी का लगा चुकी हैं,

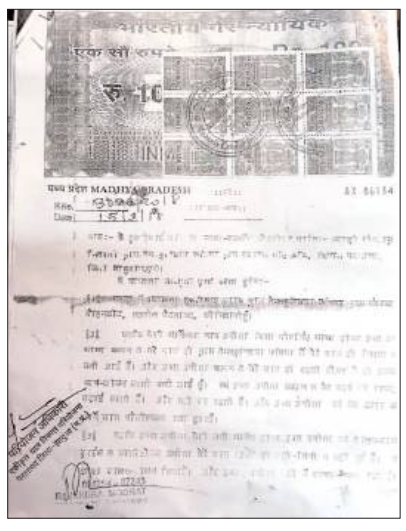

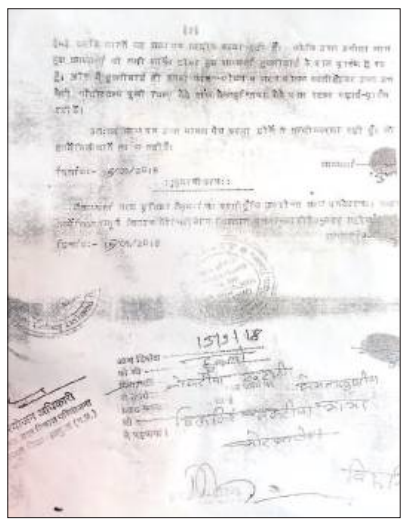

जिसमे अनिता का नाम तक नही था, तो नियम से अनिता के नानाजी जो कि राशनकार्ड में मुखिया को ही इस संबंध में शपथ-पत्र देना था कि, अनिता उसके पिता के साथ न रहकर सेमलकुण्डिया में बचपन से नाना के साथ रहती है, लेकिन सब कुछ पैसे के दम पर पहले से तय हो चुके मामले में दस्तावेज तो केवल खानापूर्ति मात्र के लिए दिए गए प्रमाण कौन क्या ओर कैसे पेश कर रहा है उससे विभाग और मामले की जांच करने वालो का कोई लेना-देना नही है। अनिता द्वारा अपने आप को सेमलकुण्डिया निवासी बताने के लिए आवेदन के साथ एक शपथ-पत्र पेश किया जो कि अनिता की मामी हुकली बाई पति स्व. कोदरिया खराड़ी निवासी सेमलकुण्डिया के नाम से 100 रुपये के स्टाम्प पर वकील द्वारा नोटरी करवा कर दिनांक 15 सितम्बर .2018 को दिया, जिसमें अनिता की मामी ने अनिता को अपना गोदी स्वरूप अपने पास बचपन से रखना बताया गया। जो कि पूरी तरह से फर्जी माना जाना था क्योंकि अनिता की मामी सेमलकुण्डिया में जरूर रहती है लेकिन अनिता की तरह अनिता के नाना नाथू पिता जेहिंग के राशनकार्ड में अनिता की मामी हुकलीबाई खराड़ी का भी नाम नही है तो फिर किस आधार पर बिना अनिता के नाम वाला अनिता के नाना का गरीबी रेखा के राशनकार्ड को मान्य किया गया। वही जब अनिता की मामी का राशनकार्ड ही नही लगा था जिसमे शपथ-पत्र अनुसार बचपन से गोदी पुत्री स्वरूप रहना बताया गया उस गोदी पुत्री का नाम न तो सेमलकुण्डिया निवासी नाना के राशनकार्ड में है, न ही सेमलकुण्डिया निवासी मामी के राशनकार्ड में, यदि अनिता भाबर अपनी मामी के साथ बचपन से रहती थी तो आवेदन के साथ अपनी मामी के नाम वाला राशनकार्ड पेश करना था जिसमे अनिता का नाम दर्ज हो या फिर नानाजी के नाम के पेश किए गए राशनकार्ड में अनिता ओर उसकी शपथ-पत्र देने वाली मामी हुकलीबाई का नाम होना था, सब कुछ देखकर भी महिला बाल विकास के अधिकारियों ने नियह्याम-कायदों को खुटी पर टांग कर फर्जी नियुक्ति कर दी।

पूरे मामले में सबसे बड़ा खुलासा करेगे इस फर्जीवाड़े के अगले भाग में।

एमडीएच बामनिया के विद्यार्थियों का नवोदय में हुआ चयन

माही की गूंज, बामनिया

विद्यालय के कक्षा 5वी की छात्रा कंचन पप्पूसिंग गामड़ का जवाहर नवोदय की कक्षा 6 टी व कक्षा 8वी के युवराज दीवानसिंग भूरिया का 9वी की प्रवेश पात्रता परीक्षा में चयन हुआ है। संस्था की उपलब्धि पर संस्था अध्यक्ष पद्मभूषण महाशय धर्मपाल जी, उपप्रधान विनय आर्य, महामंत्री जोगिंदर खट्टर, शिक्षा निदेशक श्रीमती अनु वासुदेवा, प्रोजेक्ट मैनेजर बिपिन भल्ला, गोवर्धनसिंह राठौर, जीववर्धन शास्त्री, आचार्य दयासागरजी, संजय मखोड़,

प्राचार्य प्रवीण अत्रे व संदीप बिसरिया ने बच्चो को बधाई देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की तथा पालको का संस्था के प्रति विश्वास और सहयोग हेतु आभार जताया।

गम्भीर हादसा, दुर्घटना में एक की मौत दो गंभीर

माही की गूंजए पेटलावद

पेटलावद.रायपुरिया मार्ग पर स्थित आश्रम के समीप सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई हैए जबकि दो व्यक्ति बुरी तरह से घायल हुए हैए घायलों को इलाज के लिए पेटलावद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया जहाँ गम्भीर अवस्था मे इलाज किया जा रहा है। मृतक और घायल हुए लोग कहा के है समाचार लिखे जाने तक इसकी जानकारी नही मिल सकीए किसी वाहन द्वारा टक्कर मारने की बात सामने आ रही हैं।

कंटेनमेन्ट एरिया की हुई अवधि समाप्त, रहवासियों ने ली राहत की सांस

माही की गूंज झाबुआ।

नगर में सुभाष माग्र में रहने वाले दो व्यक्तियो की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद से 10 जून को नगर के सुभाष मार्ग, बोहरा गली ओर कस्तुरबा मार्ग को जिला प्रशासन के निर्देशो के बाद से ही कंटेनमेन्ट एरिया घोषित कर उसे पुर्ण रूप से सील कर दिया गया था। जिसपर से 21 दिनो की कंटेनमेन्ट एरिया की अवधि पूर्ण होने पर पुरे क्षेत्र को कंटेनमेन्ट एरिया से जिला प्रशासन के आदेशानुसार मुक्त कर वहा से बैरिकेट्स भी हटा दिया गया है। वही सुभाष मार्ग के दो कोरोना पॉजिटिव मरीज मे से 1 के स्वास्थ्य में पूर्णतः सुधार हो चुका है वही एक इन्दौर में भर्ती है जिसका ईलाज चल रहा है।

संपादकीय

कोरोना की दवा पर सवाल

किसी भी रोग की दवा के उत्पादन और बाजार की प्रक्रिया बेहद लंबी, पेंचदार, शोधात्मक, परीक्षणपरक और सरकारी एजेंसी द्वारा प्रमाणित की जाती है। दवा से जुड़ा कोई भी चेहरा न तो प्रमाणित कर सकता है और न ही रोग के उन्मूलन का दावा कर सकता है। आखिर मानवीय जिंदगी का सवाल है। कोई भी कारोबार या बाजार इनसानी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकता। अमरीका, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों में परीक्षण की इतनी लंबी और सूक्ष्म प्रक्रिया है कि अंतिम चरण तक कुछ ही शोधात्मक प्रयास पहुंच पाते हैं। शेष नाकाम साबित हो जाते हैं अथवा उनके ट्रायल ही खरे नहीं उतरते। उन देशों में दवा या वैक्सीन को लेकर जरा-सी भी ढील, रियायत नहीं दी जाती। हालांकि आपातकाल संबंधी प्रावधान भी हैं। कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी की फिलहाल न तो कोई दवा और न ही कोई टीका है। अलबत्ता दुनिया भर में 120 से अधिक वैक्सीन पर काम जारी है। यह बेहद अहम है कि 10 वैक्सीन का इनसानों पर परीक्षण भी चल रहा है। यदि जनवरी, 2021 तक कोरोना का कोई वैक्सीन बाजार में आता है, तो वह विज्ञान की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। शायद शोधार्थी या किसी दल को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाए! चीन नेशनल बायोटेक ग्रुप की तरफ से तैयार वैक्सीन को भी आखिरी ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। कंपनी यह परीक्षण संयुक्त अरब अमीरात में करेगी। भारत में भी करीब 30 अनुसंधान कोरोना की दवा या टीके से जुड़े हैं। ऐसे नाजुक माहौल और महामारी के परिप्रेक्ष्य में बाबा रामदेव और उनके कुछ सहयोगी 'कोरोनिल' नाम से कोरोना संबंधी परहेज और उसके इलाज का दावा करने वाली औषधि को लॉन्च करते हैं, तो आश्चर्य स्वाभाविक है। कंपनी ने न तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय और न ही कोरोना पर भारत सरकार की टास्क फोर्स से स्वीकृति ली है। सवाल यह भी है कि क्या एक निजी अस्पताल और कंपनी, संबद्ध एजेंसी की अनुमति लिए बिना ही, इनसानी ट्रायल कर सकते हैं? क्या यह औषधि से जुड़े कानूनों का उल्लंघन नहीं है? इस आयुर्वेदिक दवा के शोधात्मक चरण क्या रहे, इसमें कौन से तत्त्व, कौन-सी जड़ी-बूटियां, कौन से रसायन आदि के, कितने अनुपात में, मिश्रण किए गए हैं? इस आशय का शोध-पत्र किस अंतरराष्ट्रीय पत्रिका में छपवाया गया, ताकि वैश्विक स्तर पर उसकी समीक्षा की जा सके? बेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन आयुर्वेद सरीखी देसी औषधियों को भी मान्यता देता है। हमारे देश में एलोपैथी के साथ-साथ आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों को भी पढ़ाया जाता है। विश्वविद्यालय इनकी डिग्रियां भी देती हैं। अनुसंधान भी किए जाते रहे हैं। आयुष मंत्रालय भी दवा बनाने की बात करता रहा है। अभी जो दवा बाजार में लाने का दावा बाबा रामदेव ने किया है, उसके ट्रायल पर सहयोगी मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल ने ही सवाल उठाए हैं कि जब मरीजों को ज्यादा बुखार हुआ, तो उन्हें एलोपैथी की दवा दी गई। ट्रायल को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय, आईसीएमआर, सीएसआईआर और टास्क फोर्स, किसी को भी सूचित नहीं किया गया। क्या भारत में दवा बनाने की प्रक्रिया इतनी लचर भी हो सकती है कि कोई भी महामारी की दवा बनाने और सात दिन में ठीक होने का दावा कर सकता है? बहरहाल आयुष मंत्रालय ने दवा के विज्ञापन और बिक्री पर रोक लगा दी है। सम्यक तौर पर जांच की जाएगी। गिलॉय, अश्वगंधा, तुलसी, काली मिर्च आदि हमारी प्राचीन जड़ी-बूटियां रही हैं, जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकती हैं। हम इनका प्रायः सेवन करते रहे हैं। पतंजलि और उसके सहयोगियों ने किन आधारों पर दावा किया है कि इन्हें मिलाकर बनाई गई दवा कोरोना वायरस को खत्म कर इनसान को स्वस्थ कर सकती है? इस प्रयास को कानूनी तौर पर भी चुनौती दी गई है। महाराष्ट्र और राजस्थान सरकारों ने भी बिक्री पर रोक लगाई है। सवाल यह भी है कि दुनिया की जो बड़ी-बड़ी कंपनियां अरबों रुपए खर्च करती हैं और अनुसंधान, परीक्षण पर 5-7 साल लगाती हैं, उनके वैक्सीन को आज तक स्वीकृति नहीं मिली, लेकिन 'दिव्य फार्मेसी' ने कुछ ही दिनों में करिश्मा कर दिया। नतीजतन संदेह और सवाल जरूरी हैं। फिलहाल गेंद आयुष मंत्रालय के पाले में है।

एक सलाह

अगर महानता प्राप्त करना चाहते हो, तो अनुमतियां मांगना बंद कर दो।

काम की बात

इच्छाएं, सपने, उम्मीदें, नाखून। इन्हें समय-समय पर काटते रहिए, वरना ये दुख का कारण बनते हैं।

कोरोना काल में मोदी को लेकर राहुल की तल्खी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश अभियान का शुभारंभ कर दिया है। इस बीच उन्होंने पूरे दस मिनट तक उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना की। इसे बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता। कुछ लोग कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री विदेश जाएं या देश के किसी राज्य में, वहां के मुखिया को सम्मान देते ही हैं फिर इसमें नया क्या है? इसे समझने के लिए इस बात पर गौर करना होगा कि केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को उत्तर प्रदेश में पुरजोर ढंग से क्रियान्वित कराने की हरसंभव कोशिश योगी सरकार ने की है। तभी तो प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि आपदा को अवसर के रूप में तब्दील करने के मामले में उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों से आगे है। उन्होंने कहा कि विषम कोरोना काल में उन्होंने न केवल चिकित्सा सुविधा को चाक चौबंद रखा, बल्कि प्रवासी श्रमिकों के हितों की भी रक्षा की। उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाने से लेकर उनके रोजगार तक की व्यवस्था की। दुनिया के सुपरपावर कहे जाने वाले देशों इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और स्पेन की तुलना करते हुए कहा कि इनकी कुल आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ से बहुत कम है। फिर भी वहां कोरोना संक्रमितों और उससे मरने वालों की संख्या उत्तर प्रदेश के कोरोना पीड़ितों और कोरोना से मरने वालों से कहीं ज्यादा है। उन्होंने इतना जरूर कहा कि कोरोना का इलाज जबतक मिल नहीं जाता तबतक दो गज दूरी के सिद्धांत को अपनाए रखने में ही हम सबका कल्याण है। प्रधानमंत्री कोई बात कहें और राहुल गांधी मुद्दा न बनाएं, यह संभव नहीं है। उन्होंने कहा है कि देश में नए इलाकों में कोरोना तेजी से फैल रहा है लेकिन सरकार के पास इसे हराने का कोई प्लान नहीं हैं। प्रधानमंत्री खामोश हैं। उन्होंने सरेंडर कर दिया है और बीमारी से लड़ने से इनकार कर दिया है। चीन के मामले में दिए गए अपने बयान में प्रधानमंत्री को सरेंडर तो वे बहुत पहले ही करा चुके हैं। राहुल गांधी के पास एक मोर्चा तो है नहीं। संघर्ष के लिए एकाग्रता जरूरी होती है। राहुल को राजनीति करनी है, एकाग्रता का अभ्यास थोड़े करना है। सो कभी वे समस्या की इस डाल पर तो कभी समस्या की दूसरी डाल पर उछलकूद करते नजर आते हैं। उनके हिसाब से सरकार अगर लड़े तो वह हमेशा लड़ती ही रह जाएगी और एक भी समस्या की तह तक नहीं पहुंच पाएगी।

भारत एक अरब 38 करोड़ की आबादी वाला देश है। एक अरब 38 करोड़ समस्याओं को एक व्यक्ति एक साथ एक झटके में कैसे हल कर सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंसान हैं, भगवान नहीं। प्रधानमंत्री अगर यह कह रहे हैं कि सरकार का मार्गदर्शन भारत का संविधान करता है और इसलिए सरकार धर्म, लिंग, जाति, नस्ल या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। हम 138 करोड़ भारतीयों को सशक्त बनाने की इच्छा से निर्देशित होते हैं और हमारा मार्गदर्शन भारत का संविधान करता है तो इसमें कदाचित कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन, राहुल गांधी को इतनी सामान्य सी बात समझ में क्यों नहीं आती?

इसमें संदेह नहीं कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एकदिन में सर्वाधिक 18,552 नए मामलों का सामने आना और 384 लोगों का मरना डराता है। हालात यह है कि भारत में कोरोना संक्रमितों की तादाद पांच लाख से अधिक हो गई। भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 15,685 हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक लाख तक पहुंचने में 110 दिन लगे थे लेकिन 27 जून को पांच लाख का आंकड़ा छूने में मात्र 39 और दिन लगे। यह बेहद भयावह तस्वीर है। सवाल यह है कि कोरोना के बढ़ते मामलों और उससे होने वाली मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है? अकेले मोदी सरकार या कांग्रेस समेत अन्य विपक्ष भी। प्रधानमंत्री ने जब लॉकडाउन का निर्णय लिया था तब भी कांग्रेस उनके निर्णय की आलोचना कर रही थी। फिर प्रवासी मजदूरों के पलायन मामले में उसने केंद्र सरकार को घेरना आरंभ कर दिया। सरकार चाहती थी कि जो जहां है, वहीं रहे लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में फैक्ट्रियों पर ताले जड़ दिए गए, मजदूरों को काम से निकाल दिया गया। उन्होंने जो काम किया था, उसका भुगतान तक नहीं किया गया। वर्ना वे पैदल चलने को विवश ही क्यों होते? जिस समय नरेंद्र मोदी ने देश भर में लॉकडाउन लागू किया तो राहुल गांधी में अल्बर्ट आइंसटीन की आत्मा आ गई थे। वे उन्हीं की भाषा बोलने लगे थे कि यह लॉकडाउन साबित करता है कि अज्ञानता से अधिक खतरनाक चीज केवल घमंड है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को लेकर चार ग्राफ ट्वीट किए थे। इसमें उन्होंने यह बताने और जताने की कोशिश की थी कि देश में बार-बार लॉकडाउन लगाया जा रहा है लेकिन कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है बल्कि कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा व कांग्रेस के लोग अगर वाकई सच समझ रहे होते तो उन्हें पता होता कि संक्रामक रोग भीड़ बढ़ने से फैलते हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों को घर में रहते हुए एक-दूसरे से दूरी बनाए रखने की नसीहत दी थी तो इसमें उनकी दूरदृष्टि थी। कांग्रेस ने कोरोना से निपटने के कोई प्रयास किए होते तो बात समझ भी आती लेकिन वह कोरोना से लड़ रहे लोगों का मनोबल तोड़ने में ही अपनी %शल्य% वीरता समझती रही। उसने प्रवासी मजदूरों को मदद पहुंचाने का प्रयास किया भी लेकिन उसमें भी उसने बसों की जगह ऑटो के नंबर यूपी सरकार को सौंप दिए। राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से डोनेशन प्राप्त करने का मामला हो या फिर चीन से, कांग्रेस का चेहरा बेनकाब होने लगा है। जिस बीमारी से निपट पाने में दुनिया के समर्थ और शक्तिशाली देश भी परेशान हैं। जिस बीमारी के लक्षणों पर ही दुनिया के स्वास्थ्य वैज्ञानिक एकमत नहीं हैं, जिसकी वैक्सीन या उचित दवा विकसित नहीं हो पाई है, उस बीमारी के इलाज से ज्यादा बचाव की जरूरत है। प्रधानमंत्री अगर इस रोग से बचकर रहने की बात कर रहे हैं तो इसमें आत्मसमर्पण जैसी बात कहां है? उत्तर प्रदेश में न केवल कोरोना महामारी से निपटने के प्रयास हो रहे हैं बल्कि गांवों में ही रोजगार सृजन के प्रयास आरंभ हो गए हैं।

अब पलायन गांव से शहर की ओर नहीं, शहर से गांव की ओर हो रहा है। गांव, ब्लॉक, तहसील और जिला स्तर पर उद्योग लगाने के ताने-बाने बुने जाने लगे हैं। आपदा आती ही इसलिए है कि उसका सामना किया जाए। यह पहली और आखिरी आपदा नहीं है। जब कोई नई बीमारी आती है तभी उसका इलाज ढूंढ़ा जाता है। इसमें समय लगता है। राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस को हथेली पर सरसों उगाने की बजाए धैर्य का परिचय देना चाहिए। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो सरकार को सुझाव दें कि आपके पास कोरोना से लड़ने का यह तरीका है और नहीं तो जो इसके लिए लड़ रहे हैं, उन कोरोना योद्धाओं का सम्मान बढ़ाएं। इसी में देश का कल्याण निहित है।

सियाराम पांडेय शांत, लेखक

चीन पर डिजिटल स्ट्राइक

लद्दाख में नियंत्रण रेखा पर जारी भारी तनाव के बीच केंद्र सरकार ने डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए टिक टॉक, यूसी ब्राउजर सहित चीन के 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने कहा कि ये ऐप देश की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं। आईटी मंत्रालय ने कहा कि उसे विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें मिली हैं। इनमें एंड्रायड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में कई रिपोर्ट शामिल हैं। इन रिपोर्ट में कहा गया है कि ये ऐप %उपयोगकर्ताओं के डेटा को चुराकर, उन्हें गुपचुप तरीके से भारत के बाहर स्थित सर्वर को भेजते हैं।ऽ प्रतिबंधित सूची में वीचैट, बीगो लाइव, हेलो, लाइकी, कैम स्कैनर, वीगो वीडियो, एमआई वीडियो कॉल-शाओमी, एमआई कम्युनिटी, क्लैश ऑफ किंग्स के साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफार्म क्लब फैक्टरी और शीइन भी शामिल हैं। सरकार का यह फैसला चीन के लिए तगड़ा झटका है, क्योंकि अलीबाबा, टेंसेंट, टीआर कैपिटल और हिलहाउस कैपिटल सहित चीनी निवेशकों ने 2015 से 2019 के बीच भारत के स्टार्टअप कंपनी क्षेत्र में 5.5 अरब डॉलर से अधिक निवेश किया है। इस फैसले से चीनी कंपनियों को कई करोड़ डॉलर राजस्व का नुकसान होगा। चीनी ऐप पर बैन लगाने का यह फैसला लोगों को आश्चर्यजनक नहीं लगा है। ऐसी अटकलें थीं कि चीनी कंपनियां ऐप का डेटा चीन भेज रही हैं, इसको देखते हुए उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। बहरहाल, इसे सरकार का कूटनीतिक कदम भी माना जा सकता है। चूंकि इन ऐप्स से मिलते-जुलते फीचर्स वाले ऐप की कमी नहीं, इसलिए भारत को नुकसान नहीं है। मगर चीन के लिए भारत का ऐप मार्केट न सिर्फ बहुत बड़ा था, बल्कि वह बढ़ भी रहा था। चीनी के कारोबारी हितों को नुकसान पहुंचाने वाला यह एक बड़ा फैसला है। इन ऐप्स को अब भारत में डाउनलोड और इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। जिस तरह से भारत में चीन के खिलाफ माहौल है, यह बैन कई और सेक्टर्स में भी बढ़ाया जा सकता है। यह फैसला चीनी कारोबारियों और चीन के लिए भारत की ओर से एक अहम संदेश है। भारत उन देशों में से हैं जहां इंटरनेट के दाम दुनिया में सबसे कम हैं। यहां 80 करोड़ से ज्यादा कंज्यूमर्स हैं। इनमें से आधे से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स 25 साल या उससे कम उम्र के हैं। 59 चीनी ऐप्स को बंद करके भारत ने न सिर्फ अपने इरादे जाहिर किए हैं, बल्कि चीन को साफ संदेश दिया है। टिकटॉक भारत में सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप है। इसके 12 करोड़ से भी ज्यादा ऐक्टिव यूजर्स थे। यह उन इलाकों में युवाओं के बीच खासी लोकप्रिय थी जो आमतौर पर आधुनिक सुविधाओं से अछूते हैं। टिकटॉक पर मौजूद 30 फीसदी वीडियो भारतीय यूजर्स बनाते हैं। भारतीय युवा इन चीनी ऐप्स पर अच्छा-खासा समय बिताते थे यानी चीन इनके सामने जैसा चाहता, वैसा कंटेंट परोस सकता था। भारत ने बैन लगाकर इन चीनी ऐप्स के लिए एक बहुत बड़े मार्केट के दरवाजे बंद कर दिए हैं।

चीनी ऐप्स पर बैन लगाने से भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो यूजर्स उन ऐप्स को यूज करते थे, उन्हें अब विकल्प ढूंढने होंगे जो मार्केट में कम नहीं हैं। दूसरी बात, इस बैन के चलते कई भारतीय डेवलपर्स ऐप्स बनाने के लिए उत्साहित होंगे। कई ने तो अपने ऐप्स में मेक इन इंडिया लिखना शुरू भी कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार इस बैन लागू कैसे कराएगी। भारत सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होगी जिसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से इन ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए कहा जाएगा। ऐप के यूजर्स को जल्द ही स्क्रीन पर मैसेज दिखने लगेगा कि सरकार के निर्देश पर ऐप का एक्सेस रोका गया है। गूगल प्ले स्टोर और ऐप्पल के ऐप स्टोर पर भी यही मैसेज दिखेगा। हालांकि, उन ऐप्स का इस्तेमाल जारी रह सकता है जिन्हें ऐक्टिव इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है। हालांकि इन ऐप्स को अब भारत में डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा।

सिद्धार्थ शंकर, लेखक

विस्तार जरूरी कि नेतृत्व परिवर्तन?

मध्यप्रदेश में भाजपा की जोड़-जुगाड़ वाली सौ दिन की सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी के साथ ही ये चर्चा भी चल पड़ी है कि मध्यप्रदेश में मंत्री मंडल का विस्तार जरूरी है कि नेतृत्व परिवर्तन? भाजपा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संकट मोचक ही अब उनके उत्तराधिकारी बनने के लिए लार टपकाते दिखाई दे रहे हैं।

सारे घटनाक्रम पर नजर डालें तो सार नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौथी बार सत्ता में आने के बाद अब तक सुरक्षित अनुभव नहीं कर रहे हैं। उनकी सौ दिन की सरकार जैसे-तैसे पांच मंत्रियों के सहारे चली है और अब उसे गति देने के लिए एक्सीलेटर उनके हाथ में नहीं दिखाई दे रहा। समझा जाता है कि भाजपा के अनेक नेताओं के साथ ही भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अब शिवराज सिंह चौहान के साथ अटपटा अनुभव कर रहे हैं। दिल्ली में मौजूद शिवराज सिंह चौहान नए मंत्रियों की सूची लेकर गए हैं, लेकिन इस बीच उनको ही हटाए जाने की अटकलें लगने लगीं। हद तो तब हुई जब भाजपा के एक समूह ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को शिवराज सिंह चौहान की जगह मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में संघ परिवार के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कृपा के घेरे में हैं इसलिए इन अफवाहों को बल भी मिला। तोमर बीते पंद्रह साल से प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। एक समय राजनाथ सिंह के कार्यकाल में वे मुख्यमंत्री बनते-बनते रह भी गए थे। भाजपा के अंदरूनी सूत्रों का कयास है कि पार्टी के महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय के अलावा मौजूदा गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा भी इस फिराक में हैं कि यदि उन्हें विजयवर्गीय और सिंधिया का समर्थन मिल जाये तो वे शिवराज का ताज अपने सर पर सजा लें। डॉ. मिश्रा को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का आशीर्वाद प्राप्त है इसलिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उनके खिलाफ नहीं जा सकते। आपको याद होगा कि डेढ़ साल पहले मप्र के दौरे पर पार्टी अध्यक्ष की हैसियत से भोपाल आये अमित शाह डॉ. मिश्र का आतिथ्य स्वीकार चुके हैं। दिल्ली से एक खबर ये भी चली है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थक में से दो और विधायको को मंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं, हालांकि ये विधायक भाजपा के ही हैं, लेकिन सिंधिया के साथ खड़े नजर आने लगे हैं। सिंधिया के भाजपा से राज्यसभा सदस्य बनते ही अब प्रदेश भाजपा में उनकी एक नई लॉबी बन गई है, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के लिए चुनौती बन गई है। आपको याद होगा कि शिवराज ने ही विधानसभा चुनाव के समय माफ करो महाराज का नारा दिया था। लगता है कि अब राज्यसभा पहुंचते ही सिंधिया ने अपने समर्थकों के माध्यम से माफ करो शिवराज का नारा बुलंद करा दिया है। सूत्रों का कहना है कि सिंधिया शिवराज के स्थान पर डॉ. नरोत्तम मिश्रा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मुख्यमंत्री बनाए जाने के पक्ष में हैं, उनके लिए ये दोनों नेता शिवराज सिंह चौहान के मुकाबले ज्यादा मुफीद हैं। दोनों ने कभी न कभी महल का संरक्षण पाया है इसलिए वे महल के प्रति श्रद्धानवत भी रहेंगे। शिवराज सिंह के प्रति महल की धारणा अलग है। सूत्रों का कहना है कि मध्यप्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन करने से भाजपा हाईकमान फिलहाल बचना चाहता है, लेकिन यदि बात न बनी तो इस हिचकिचाहट को दूर कर भी फैसला किया जा सकता है। ये फैसला मुमकिन है कि आजकल में ले लिया जाए। सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा सक्रिय मुख्यमंत्री चाहता है। ऊर्जा के स्तर पर शिवराज सिंह अब पहले जैसे नहीं दिखाई देते। इस पैमाने पर डॉ. नरोत्तम मिश्र ही फिट बैठते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर भी शायद अब इस पैमाने पर खरे न उतरें। वैसे भी उनकी छवि अब केंद्रीय नेता की बन चुकी है। मध्यप्रदेश में दलबदल के बाद बनी भाजपा की सरकार जनादेश की सरकार नहीं है, इसे धनादेश की सरकार कहा जाता है। 24 सीटों के लिए होने वाले उप चुनाव के बाद शायद इसमें जनादेश शब्द एक बार फिर से जोड़ लिया जाए। जब तक ये उपचुनाव भाजपा के पक्ष में नहीं जाते तब तक सरकार के सर पर अस्थिरता की तलवार लटकी ही रहेगी। मंत्रिमंडल का विस्तार या नेतृत्व परिवर्तन भी इसे हटा नहीं सकता।

राकेश अचल, वरिष्ठ पत्रकार

जयंतीलाल भंडारी, अर्थशास्त्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए 26 जून को 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान' का शुभारंभ कर दिया। वास्तव में, यह देश में कोरोना काल में रोजगार के लिए शुरू किया गया सबसे बड़ा अभियान है, जिस पर अपने राज्य लौटे मजदूरों के साथ ही देश की भी नजरें टिकी हैं। इसके तहत देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में करीब सवा करोड़ लोगों को विभिन्न परियोजनाओं के तहत रोजगार नसीब होगा।

वस्तुतः उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान' का मुख्य लक्ष्य प्रदेश में वापस आए प्रवासी कामगारों को उनके ही क्षेत्र में हुनर व रुचि के आधार पर रोजगार प्रदान करने, स्थानीय स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने व रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक संगठनों और अन्य संस्थानों को साथ जोड़ना है। जब लोग भी रोजगार के लिए सरकार की ओर देख रहे हैं, तब यह एक सराहनीय कदम है। देश के विभिन्न राज्यों में भी रोजगार निर्माण के लिए ऐसे विशेष अभियानों की जरूरत दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के इस अभियान से अन्य राज्यों को भी यथोचित प्रेरणा मिलेगी।

आज निजी क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के प्रयासों के साथ ही सरकारी स्तर पर ऐसी पहल बहुत जरूरी है। विशेष अभियानों के अलावा सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर तत्परता के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने पर भी ध्यान देना होगा। सरकार ने विगत 14 मार्च को संसद में बताया है कि रेलवे, रक्षा, डाक सहित अन्य सरकारी विभागों में करीब 4.76 लाख भर्तियां की जानी हैं। इनमें से यूपीएससी, एसएससी और रेलवे भर्ती बोर्ड के जरिए 1.34 लाख और रक्षा विभाग में 3.4 लाख खाली पदों को भरा जाना है। केंद्र सरकार के अलावा राज्यों सरकारों के भी लाखों पद रिक्त हैं। सरकार के स्तर पर रिक्त पदों को भरने के लिए भी विशेष अभियान चलाने की जरूरत है। विशेष रोजगार अभियान को कुछ बहुत जरूरतमंद जिलों में चलाने के साथ ही मनरेगा में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। काम मांगने वाले लोगों को रोजगार देकर समाज को व्यापक संकट से बचाया जा सकता है। ज्यादा लोगों को रोजगार देने से अर्थव्यवस्था को भी सीधे फायदा होगा। इससे मांग और आपूर्ति बढ़ेगी, विकास दर में तेजी आएगी।

यह साफ दिखाई दे रहा है कि कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों और कर्मचारियों के सामने रोजगार संकट ज्यादा बढ़ा है। इस दौर में देश में बेरोजगारी की चुनौती कितनी तेजी से बढ़ी है, इसका अनुमान प्राइवेट थिंक टैंक 'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी' द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। इसके मुताबिक, भारत में जनवरी 2020 में बेरोजगारी दर 7.2 प्रतिशत थी, यह फरवरी में 7.8 प्रतिशत और मार्च में 8.7 प्रतिशत हो गई। यह अप्रैल 2020 में 23.52 फीसदी तथा मई 2020 में 23.48 फीसदी हो गई। यद्यपि लॉकडाउन समाप्त होने के साथ-साथ बेरोजगारी दर में कमी बताई जा रही है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। युवाओं को अपना मनोबल और व्यवस्था में विश्वास बनाए रखना चाहिए। चुनौतियां बढ़ी हैं, पर स्थिति ऐसी बुरी भी नहीं है कि जिससे उबरना मुश्किल हो। अच्छा रोजगार चाह रहे लोगों को किसी न किसी चीज में विशेषज्ञता या कार्य कुशलता के लिए प्रयास जरूर करना होगा। विभिन्न वैश्विक रिपोर्टों में तथ्य उभरकर सामने आ रहा है कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर में जोरदार गिरावट होगी, लेकिन आगामी वित्त वर्ष 2021-22 में देश की विकास दर में तेजी दिखाई देगी। भारत में रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। ऐसे में, दुनिया के मानव संसाधन शोध संगठनों का कहना है कि कोविड-19 की चुनौतियों से भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कहीं शीघ्रतापूर्वक बाहर निकलेगी और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। पिछले दिनों न्यूयॉर्क के मैनपॉवर ग्रुप द्वारा प्रकाशित 44 देशों के रोजगार के वैश्विक सर्वेक्षण के मुताबिक, कोविड-19 के बीच रोजगार के मामले में सकारात्मक परिवेश दिखाने वाले दुनिया के चार शीर्ष देशों में भारत भी शामिल है। भारत के अलावा केवल जापान, चीन और ताइवान में रोजगार को लेकर सकारात्मक परिदृश्य पाया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद और कोरोना काल के बीच भारत में जुलाई से सितंबर 2020 की तिमाही में पांच सेक्टरों- खदान, निर्माण, वित्त, बीमा और रियल एस्टेट में नौकरियों के नए रास्ते खुलेंगे। प्रमुख मानव संसाधन कंपनी टीमलीज की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, देश के चार महानगरों, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को छोड़कर मेट्रो के रूप में उभरते शहरों- बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, चंडीगढ़, कोच्चि, कोयंबटूर, आदि में रोजगार बढ़ेंगे। इन शहरों में हेल्थ, फार्मा, ई-कॉमर्स, एफएमसीजी, कृषि, एग्रो-केमिकल्स, ऑटो-मोबाइल्स और इनसे जुढ़ी सेवाओं, बीपीओ सेवाएं, निर्माण तथा रिएल एस्टेट व ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार के मौके तेजी से बढ़ेंगे। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दिए गए आर्थिक पैकेज से देश के उद्योग-कारोबार क्षेत्र को जो लाभ मिलेगा, उससे रोजगार के मौके बढ़ेंगे। युवाओं को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कोविड-19 के बाद आने वाले वर्षों में दुनिया के कई देशों में अर्थव्यवस्थाओं को संभालने के लिए प्रशिक्षित युवा हाथों की कमी होने वाली है। मानव संसाधन परामर्श संगठन कार्न फेरी की रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां दुनिया में 2030 तक कुशल श्रम बल का संकट होगा, वहीं भारत के पास 24.5 करोड़ अतिरिक्त कुशल श्रम बल होगा। साल 2030 तक दुनिया के 19 विकसित व कई विकासशील देशों में 8.52 करोड़ कुशल श्रम शक्ति की कमी हो जाएगी। ऐसे में,भारत इकलौता देश होगा, जिसके पास 2030 तक जरूरत से ज्यादा कुशल श्रम बल होगा। भारत दुनिया के तमाम देशों में कुशल श्रम बल को भेजकर फायदा उठा सकेगा।

निजी क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं का भविष्य उज्ज्वल है, लेकिन इससे सरकारों की जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती। सरकारों को अपनी रोजगार योजनाओं को चाक-चौबंद तरीके से चलाकर समाज में राहत का भाव बनाए रखना होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

पीटीआई को सरकारी धमकी

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) देश की सबसे पुरानी और सबसे प्रामाणिक समाचार समिति है। मैं दस वर्ष तक इसकी हिंदी शाखा 'पीटीआई–भाषा' का संस्थापक संपादक रहा हूं। उस दौरान चार प्रधानमंत्री रहे लेकिन किसी नेता या अफसर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह फोन करके हमें किसी खबर को जबर्दस्ती देने के लिए या रोकने के लिए आदेश या निर्देश दे लेकिन अब तो प्रसार भारती ने लिखकर पीटीआई को धमकाया है कि उसे सरकार जो 9.15 करोड़ रु. की वार्षिक फीस देती है, उसे वह बंद कर सकती है। यह राशि पीटीआई को विभिन्न सरकारी संस्थान जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन, विभिन्न मंत्रालय, हमारे दूतावास आदि, जो उसकी समाचार-सेवाएं लेते हैं, वे देते हैं। यह धमकी वैसी ही है, जैसी कि आपात्काल के दौरान इंदिरा सरकार ने हिंदी की समाचार समितियों- 'हिंदुस्थान समाचार' और 'समाचार भारती' को दी थी। मैंने 'हिंदुस्थान समाचार' के निदेशक के रुप में इस धमकी को रद्द कर दिया था। मैं अकेला पड़ गया। मेरे अलावा सबने घुटने टेक दिए और इन दोनों एजेंसियों को उस समय पीटीआई में मिला दिया गया। क्या पीटीआई को दी गई यह धमकी कुछ वैसी ही नहीं है? मैं पीटीआई के पत्रकारों से कहूंगा कि वे डरें नहीं। डटे रहें। 1986 में बोफोर्स कांड पर जब जिनीवा से चित्रा

आखिर कछुआ जीत गया !

संदर्भः डीज़ल ने पेट्रोल को पछाड़ा

डॉ. अरविन्द प्रेमचंद जैन, लेखक

किसी भी मनुष्य को अधिक घमंड नहीं करना चाहिए और न अहम। हमेशा समय बलवान होता हैं। समय को करवट बदलने में समय नहीं लगता। समय के कारण बड़े बड़े पहलवान हार जाते हैं और पिद्दी पहलवान जीत जाते हैं। देखो रावण का घमंड नहीं रहा ,उनको भी हार का सामना कर पड़ा।

ऐसा को व्यक्ति हैं जो हमेशा जीता हैं ,जो हमेशा जीतता हैं उसे हार का डर लगा रहता हैं ,जो हारा हुआ हैं वह निडर रहता हैं। जो शिखर पर होता हैं उसे धरातल में आने का डर रहता हैं और जो धरातल पर हैं उसे किस बात का डर।

कहते हैं शब्द के बाण जिंदगी भर दिल में लगे रहते हैं। शरीर का घाव भर जाता हैं पर शब्द के बाण जिंदगी भर नहीं भरते। मात्र अंधे कि औलाद अंधी होती हैं पर महाभारत हो गया था। रूपवती होने से सीता का अपहरण हुआ और जिंदगी भर के लिए रावण कलंकित हुआ। पार देश कि स्तरहीन घटिया राजनीति में अब तो शब्दों का क्या ,बमों का भी असर नहीं पड़ता।

जब विपक्ष में रहते हैं तब कहते हैं, सरकार को ऐसा करना चाहिए और जब स्वयं सत्ताशीन होते हैं तब कहते हैं हम देखेंगे, करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ?

वर्तमान में जो सत्ताधारी हैं उनके वर्ष 2013-14 के भाषण सुनें तो तत्कालीन सरकार को बिना पानी के कोसते रहे। न केवल वे नेता वरन उनके चम्मचे या चाटुकार चाहे डबल श्री हो या सलवार धारी बाबा। उस समय ऐसा लग रहा था कि यदि सरकार बनी तो केरोसीन ,पेट्रोल और डीज़ल कि नदियां देश में बहा देंगे। उस समय इतने आसूं बहाये, छाती पीटी और चटखारे लेकर तत्कालीन मुख्य मंत्री गुजरात अपनी लोकप्रियता पर इतना गुमान कर रहे थे कि शायद जो बोल रहे थे वह करेंगे ,पता नहीं कुर्सीनशीन होने के बाद सिर्फ दहाड़ते रहे हुए धरातल पर शून्य, कारण जीत का उत्साह में होश नहीं रहा।

अपने मुंह मियाँ मिठ्ठू बनने वाले अपनी कसीदा सुनते रहे और सुनाते रहे। लगने लगा जैसे विश्व विजेता बनेगे। विपक्ष को हमेशा बेइज्जत किया। होता भी हैं और होना भी चाहिए

,क्योंकि चुनाव लड़े नहीं जाते प्रबंधन से जीता जाता हैं। जनता में बहुत उत्साह हैं और भविष्य में भी रहेगा विश्व गुरु बनना हैं और उस दिशा में हम अग्रसर हैं।

पता नहीं किस मुहूर्त में पद ग्रहण किया उस दिन से देश में गिरावट का सिलसिला चल रहा हैं और सबसे अधिक वह व्यक्ति बहुत मुर्ख माना जाता हैं जो अपने विरोधियों के नाम लेकर कोसता हैं। विगत 6 वर्ष से अधिक समय में प्रधान सेवक ने सबसे अधिक लोकप्रिय बनाया गांधी-नेहरू परिवार को। सब जगह इसी परिवार का बखान। दुश्मन दोस्त जैसा हो गया। क्या करे कुछ नहीं किया तो पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ो। उन्होंने कुछ नहीं किया,उन्होंने ये गलत किया, पर खुद ने क्या कर लिया? हवा हवाई जुमलेबाज़ी।

मतलब की बात पर आये जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे देश में हमेशा कछुआ जीतता रहा और इस बार भी जीता ।पेट्रोल हमेशा सबसे महंगा रहता था ,पर वर्तमान सरकार की अनुकम्पा से डीज़ल उससे भी आगे निकल गया ।इस बिंदु पर सरकार के पास बहुत दलीलें हो सकती हैं और अपनी कमजोरी छिपाने पुरानी सरकारों की नाकामियों की दलील दी जा सकती हैं ।वर्तमान सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में हैं ,पूरा समर्थन ,बहुमत होने के बाद कब तक पिछली सरकार को कोसेंगे ।फूलमाला पहनने आगे और उस कुछ के लिए पीछे ऐसा क्यों ?

इससे कितने फायदे होंगे ---पहले किसानों को और अधिक मात्रा में आत्महत्या करना पड़ेगा,मंहगाई के कारण शासन में बैठे मंत्री नेता सचिवों को अपने जेब से थोड़ी खर्च करना पड़ता हैं ,उसके बाद माल ढुलाई की लगत बढ़ेंगी ,जिससे सामग्रियां महंगी होगी ,आम नागरिक ख़ास हो जायेगा ।रेल बसों का भाड़ा बढ़ेगा ,निजी वाहन खड़े रहेंगे या मन मार कर चलाएंगे ।हर सामग्री का महंगा होना ,यानी सरकार की विफलता का प्रतीक हैं ।

युध्य के कारण का बहाना बनाकर जनता को चुप करेंगे पर जनता कैसे भरण पोषण करेंगी ।सत्ताधारियों को इसलिए फर्क नहीं पड़ता ,क्योकि उनकी निगाह में यक्षणी शक्ति होती हैं ।उनके पास अनंत शक्ति का भण्डार होता हैं ।कभी झोला उठाकर बाज़ार तो जाना नहीं पड़ता ।मात्र अपने सुरक्षित बंगलों में बैठकर चिंतन करते हैं ।

इस विषय पर सरकारों को जनहित में सोचना चाहिए ,क्या करे भारत इतना बड़ा देश हैं और जनता में आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं हैं ,विपक्ष शक्तिहीन हैं इसका फायदा मिल रहा हैं।

इस प्रकार की असफलताएं भविष्य के लिए लाभकारी होंगी ।कारण जनता पछता रही हैं ।पुनः मूषको भवः।यही रफ़्तार रही तो हम हर क्षेत्र में अग्रणी रहेंगे चाहे शिक्षा ,स्वास्थ्य सड़क बिजली ,पानी इत्यादि ।गरीब रहेंगे नहीं तो गरीबी मिट जाएँगी ,रोजगार की जरुरत नहीं कारण ,रोजगारी ही बेरोजगार हो रहे हैं ।सब तरफ अमन चैन हैं ।

सब कुछ हमारे देश में रोटी नहीं तो क्या ?
वादा लपेट लो लंगोटी नहीं तो क्या ?

एकता और शक्ति के संदेश को घर से राष्ट्र तक विस्तार की आवश्यकता

विवेक रंजन श्रीवास्तव, लेखक

फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का एक प्रसिद्ध कथन है ठइतिहास में जिस बिंदु पर हम खड़े हैं वो वादों और खतरों से भरा है। दुनिया या तो एकता और व्यापक रूप से साझा समृद्धि की ओर बढ़ेगी या इससे अलग हो जाएगीठ।

जब भी मानवीय एकता में कोई हलचल पैदा हुई है दुनिया ने बहुत आतंक और अस्थिरता देखी है। प्रायः ही नोबल शांति पुरस्कार वैश्विक मंच पर मानवीय एकता के विस्तार हेतु किये गये कार्यो के लिये दिया जाता रहा है।

भारतीय संदर्भो में एकता का बड़ा महत्व है क्योकि भारत पाकिस्तान का बंटवारा कर अंग्रेजो ने धर्म के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण किया था, जबकि शेष भारत विभिन्नता में एकता के स्वरूप में मुखरित हुआ है। देश में अनेको भाषायें, ढ़ेरों बोलियां, कई संस्कृतियां, विभिन्न धर्मावलम्बी, क्षेत्रीय राजनैतिक दल हैं। यही नही नैसर्गिक दृष्टि से भी हमारा देश रेगिस्तान, समुद्र, बर्फीली वादियों और मैदानी क्षेत्रो से भरा हुआ है। हम विविधता में देश के रूप में एकता के जीवंत उदाहरण के लिए सारी दुनियां के लिये पहेली है। जाति, वर्ग, धर्म आदि अनेक व्यैक्तिक मान्यताओं में भेद होने के बावजूद एकता और परस्पर शांति, प्रेम सद्भाव के अस्तित्व पर हमारी शासन व्यवस्था और समाज का ताना बाना केंद्रित है।विविधता में यह एकता ही राष्ट्र की शक्ति है। विशिष्ट रीति-रिवाजों के साथ लोग हमारे देश में शांत तरीके से अपना जीवनयापन करते हैं, यहाँ मुसलमान, सिख, हिंदू, यहूदी, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी सहअस्तित्व के संग जोश और उत्साह के साथ अपने धार्मिक त्यौहार मनाते हैं।

जब इस तरह का परस्पर सद्भाव होता है तो विचारों में अधिक ताकत, बेहतर संचार और बेहतर समझ होती है। अंग्रेजों के भारत पर शासन के पहले दिन से लेकर भारत की आज़ादी के दिन तक भारतीयों की आजादी का संघर्ष सभी समुदायों की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अलग होने के बावजूद जनता के संयुक्त प्रयास किए बिना आजादी संभव नहीं थी। जनता सिर्फ एक लक्ष्य से प्रेरित थी और यह भारत की आजादी प्राप्त करने का उद्देश्य था। यही कारण है कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम विविधता में एकता का एक अप्रतिम उदाहरण है।

आजादी के तुरंत बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बुद्धिमत्ता से देश की 565 छोटी बड़ी रियासतो का संविलयन भारत गणराज्य में करवाया कि वे एकता के प्रतीक पुरुष बन कर उभरे। कृतज्ञ राष्ट्र ने गुजरात में नर्मदा पर बने सरदार सरोवर बांध के जलाशय के बेट टापू पर सरदार पटेल की 182 मीटर ऊँची प्रतिमा का निर्माण किया है, जिसे स्टेच्यू आफ यूनिटी नाम दिया गया है। गर्व की बात है कि यह मूर्ति दुनिया की अब तक स्थापित मूर्तियो में सबसे बड़ी है। एकता वह अद्भुत शक्ति है जो हमें नैतिक रूप से समृद्ध करती है। उदाहरण के लिए एक परिवार की इकाई में परस्पर प्रेम, बंधन और सद्भाव एकता का प्रतीक हैं, इन्ही मूलभूत भावनात्मक लगावों के कारण सारा परिवार एक छत के नीचे एक साथ रहता है।परिवार जन एक-दूसरे के साथ अपनी परेशानियों और दुःखों को, खुशियो को साझा करते हैं यही एकता की मूल शक्ति है। एकता का महत्व निर्विवाद है, पानी की बूंदें ही महासागर बना देती हैं और बूंदें ही अथाह जल की एकता की इकाई हैं।एकता एकल और संयुक्त लक्ष्य के लिए एकजुटता व सद्भाव की भावना है।

एकता के संदर्भ में किसान और उसके पुत्रों की प्रसिद्ध कहानी हम सब ने सुनी है, किसान ने अपने कट्टरपंथी व परस्पर बिखरे हुये विचारो वाले 4 पुत्रों को लकड़ी के एक बंडल को तोड़ने के लिए कहा और बेटे ऐसा करने में विफल हो गए। बाद में किसान ने उन्हें प्रत्येक छड़ी को अलग-अलग तोड़ने के लिए कहा और उन्होंने बिना कोई अतिरिक्त प्रयास किए ही अलग अलग लकड़ी को तोड़ दिया। इस उदाहरण से पिता ने उन्हें महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि अगर वे एकजुट होकर खड़े रहे तो कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और अगर विभाजित हो गए तो वे बिखर कर टूट जाएंगे। तार्किक दृष्टि से पूछा जा सकता है कि आखिर वह रस्सी किस चीज की बनी होती है जिससे लकड़ियों के बंडल को बांधा गया था, इसका सरल उत्तर ही एकता में शक्ति प्रदर्शित करता है, वह रस्सी प्रेम, सद्भाव परस्पर सामंजस्य और एक दूसरे के लिये भावनात्मक लगाव के सूत्रो से बनी होनी चाहिये, तभी एकता शक्ति में रूपांतरित होती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मानव जीवन के प्रत्येक चरण में एकता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जबकि घृणा और ईर्ष्या एकता को कमज़ोर करती है जिसका परिणाम बर्बादी और तबाही ही होता है। एकता समूह के सभी सदस्यों के लिए समान अधिकार प्रदान करती है। एक साथ खड़े रहना कार्यस्थल, निजी जीवन और विभिन्न संगठनों में हमारे मनोबल को बढ़ाता है। एकता संबंधों को मज़बूत करने और टीम वर्क पर जोर देने में मदद करती है, जिससे प्रदर्शन में सुधार, काम की गुणवत्ता और जीवन शैली बेहतर परिणामी बन जाती है। आईये हम सब आत्म चिंतन करें और संकल्प लें कि हम घर, परिवार अपने परिवेश समाज और देश के व्यापक हित में सदैव एकता पूर्ण व्यवहार करेंगे।

चीन पर भारत की दुविधा ?

गलवान घाटी की घटना के बाद चीन ने अपना रुख और सख्त कर दिया है। बल्कि पिछले हफ्ते तो चीन के विदेश और रक्षा मंत्रालयों- दोनों ने एक साथ भारत पर निशाना साधा। उन्होंने गलवान वैली में 15 जून को हुई हिंसक वारदात के लिए भारत को दोषी ठहराया। साथ ही भारत पर द्विपक्षीय समझौतों और अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करने और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर टकराव पैदा करने का इल्जाम लगाया। हैरत इस बात पर हुई कि इन बयानों का जवाब देने में भारत ने 24 घंटों से भी ज्यादा समय लगा दिया। आखिरकार जब जवाब आया भी, तो उससे सिर्फ एक संकेत मिला कि गलवान वैली और दूसरी जगहों पर चीनी घुसपैठ को भारत ने स्वीकार नहीं किया है। हालांकि इसके पहले प्रधानमंत्री के बयान से जो भ्रम पैदा हुआ, वह पूरी तरह छंटा नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारतीय जमीन पर ना तो कोई घुस आया है, और ना ही कोई घुसा हुआ है। बहरहाल, भारतीय विदेश मंत्रालय ने आखिरकार एक लंबा वक्तव्य जारी किया। उसमें चीन को चेतावनी दी गई कि मौजूदा स्थिति अगर ऐसी ही रही तो इससे दोनों देशों के बीच के रिश्तों को नुकसान होगा।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि मुद्दे के केंद्र में मामला यह है कि मई की शुरुआत से ही चीन की तरफ से वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ साथ सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी और हथियारों की तैनाती हो रही है। यह 1993 के बाद से दोनों देशों के बीच हुए समझौतों के अनुकूल नहीं है। मंत्रालय ने चीन के सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों की गश्त में अवरोध पैदा करने की निंदा की। कहा कि ये उन सभी मानकों का पूरी तरह से अनादर है, जिन पर दोनों देशों के बीच सहमति रही है। मगर इन बातों का चीन पर कोई असर नहीं हुआ है। बल्कि उसके बयान और जमीनी गतिविधियों से साफ है कि वह भारतीय जमीन पर हालिया कब्जे को खाली करने के मूड में नहीं है। बल्कि उसने वहां स्थायी निर्माण शुरू कर दिए हैं। भारतीय बयान के बाद एक भारतीय समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में भारत में चीन के राजदूत सून वीडॉन्ग ने कहा कि इस स्थिति की जिम्मेदारी चीन पर नहीं है, क्योंकि चीनी सिपाहियों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा कभी पार ही नहीं की। जाहिर है, चीन जहां तक आ गया है, उसे अपना क्षेत्र बता रहा है। भारत इस स्थिति पर दुविधाग्रस्त दिखता है। इसका फायदा चीन उठा रहा है।

थांदला - चिकित्सक दिवस पर नगरीय पत्रकार समिति द्वारा स्थानीय सिविल अस्पताल के डाक्टरो का अस्पताल पहुचकर स्वागत सम्मान किया। नगर के समस्त पत्रकारो ने षासकीय चिकित्सालय के डा कमलेष परस्ते, डा मनीष दुबे, डा अनिल राठौर,डा प्रदीप भारती डा संजय कटारा का पुष्पो से सम्मान करते हुवे उनके द्वारा वर्षो से नगर को दी जा रही सेवाओ के लिये उनको साधुवाद दिया तथा कोरोनाकाल मे उनके अमूल्य योगदान के लिये नगर की ओर धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर सुधीर षर्मा,चन्दु प्रेमी, अक्षय भटट,सिद्धु कांकरिया, मनोज उपाध्याय,आत्माराम षर्मा,मनीष अहिरवार, समकित तलेरा,राजु धानक, राजेष डामर मनीष वाघेला आदि उपस्थित थे।

शासकीय उचित मूल्य की दूकानों पर हो रही कालाबाजारी

कोरोना संकट के समय सैल्समेनों की हुई चॉदी

माही की गूंज झाबुआ।

जिले सहित नगर मे इन दिनों शासकीय उचित मूल्य की दूकानो मे जमकर कालाबाजारी की जा रही है। वही जहा एक ओर प्रदेश सरकार की योजना के अन्तर्गत शासकीय उचित मूल्य की दूकानो पर 5 किलो चावल और एक किला चने की दाल को वितरण की प्रक्रिया बनाई गयी थी, जिस पर से इन उचित मूल्य की दूकानो पर सैल्समैनो के द्वारा कालाबाजारी कर चने की दालो का वितरण ही नही किया गया। वही चने की इन दालो को बाजारो मे अन्य दूकानदारो को बेचकर सैल्समैनो ने बडा मुनाफा कमाया है, इसी के साथ ही इन सैल्समैनो के द्वारा उचित मूल्य की दूकानो पर कैरोसिन की भरपूर आवक होने के बाद भी इनके द्वारा जमकर कालाबाजारी की जा रही है। लॉकडाउन के चलते कालाबाजारी कर सैल्समैनो की चॉदी हो गई। वही इन सैल्समैनो के द्वारा कैरोसिन के उपभोक्ताओ को बेवकूफ बनाकर उन्हे नही दिया जा रहा है। वही उनके द्वारा नगर एवं जिले भर मे स्थित छोटी-छोटी होटलो से लेकर बडी होटलो तक कैरोसिन का सप्लाय कर

उन्हे बेचा जा रहा है। वही खाद्य विभाग का इस ओर कोई ध्यान नही दिया जा रहा है। इसके चलते नगर में उपभोक्ताओ को विगत कई महिनो से कैरोसिन नही मिल रहा है। कई बार सैल्समैनो के द्वारा उपभोक्ताओ को यह कहकर टाल दिया जाता है कि उनके घरो मे तो गैस जल रही है उन्हे नही मिल सकता। जिस पर से उस उपभोक्ता के नाम का कैरोसिन सैल्समैनो के द्वारा काली कमाई के रूप मे सामने आकर उसे बेचा जा रहा है। इतना ही नही कई सैल्समैनो के द्वारा अन्य कई सामानो मे भी हैराफैरी कर शासन का चुना लगाया जा रहा है। पूर्व मे प्रदेश सरकार के द्वारा अंगूठा लगाकर मशीन से उपभोक्ताओ को राशन की सुविधा प्रदान करने के आदेश दिये गये थे जिससे की इस प्रकार की हो रही कालाबाजारी को रोका जा सके। लेकिन ग्रामीण अंचलो मे यह सुविधा सही प्रकार से कार्य नही कर पाने के एवज मे इस सुविधा को प्रदेश सरकार के द्वारा बंद करना पडा। क्योकि ग्रमीणो के द्वारा कडी मेहनत करने के कारण उनके हाथो की उंगलियो के साथ ही अंगूठे की रेखाये भी मिट जाती है। जिससे की थंब मशिन उसे नही ले पाती थी ओर उपभोक्ताओ को राशन से वंछित रहना पडता था। इसके लिये इस प्रकार की सुविधा को भी बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी सैल्समैनो के द्वारा राशन की दूकानो से खाद्य सामग्रीयो की कालाबाजारी थमने का नाम नही ले रही है। जिसके कारण उपभोक्ताओ को अनाज मिलने मे परेशानियो का सामना करना पड रहा है। इस ओर जिला प्रशासन को ध्यान देने की दरकार है।

कार्यरत और फॉलेन आउट अतिथि विद्वानों की हो फिर एक साथ च्वाईस फिलिंग, 2000 फॉलेन आउट 7 माह से वेटिंग में

माही की गूंज झाबुआ।

महाविद्यालयों में कार्यरत 2563 अतिथि विद्वानों को शिवराज सरकार ने एकबार फिर 12 माह के लिए 1 जुलाई से आंमत्रित कर लिया है। जबकि 2000 के करीब फॉलेन आउट 7 माह से सेवा में आने का इंतजार कर रहें हैं। अतिथि विद्वान मोर्चा के मीडिया प्रभारी शंकरलाल खरवाडिया का कहना है कि, 17 दिसंबर 2019 के नवीन निर्देशानुसार अतिथि विद्वानों को सम्पूर्ण 12 माह के लिए आंमत्रित करने का उल्लेख है। उसके बाद रिक्त पदो पर फिर से च्वाईस करवाकर अगले 12 माह के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसलिए कार्यरत और फॉलेन आउट की एक साथ फिर से च्वाईस फिलिंग करवाना चाहिए। जिससे मेरिट के अनुसार फिर से कॉलेज आवंटित हो सकें। उसके बाद नियमितीकरण प्रक्रिया को केबिनेट में लाकर पारित करना चाहिए, क्योंकि पिछले साल कमलनाथ सरकार में भ्रष्ट सहायक, प्राध्यापक भर्ती 2017 से नियुक्ति देते समय अतिथि विद्वानों के अध्यापन अनुभव, मेरिट अंक और श्रेणी का ध्यान रखे बिना ही नियुक्ति दे दी थी। जिससे उच्च योग्यताधारी फॉलेन आउट होकर बेरोजगार है और कम अंक वाला लगातार सेवा में है। अब तक शिवराज सरकार ने केवल झूठी सांत्वना के अलावा कुछ नहीं दिया है।

वहीं कमलनाथ सरकार में 6 मार्च को 1120 पदो पर च्वाईस फिलिंग करवा ली थी, लेंकिन सत्ता परिवर्तन के बाद से शिवराज सरकार ने 101 दिन होने पर भी लिस्ट जारी नहीं की। सबको रोजगार मुहैया कराने वाली शिवराज सरकार में ही दो अतिथि विद्वान हाल ही में फांसी लगाकर आत्महत्या कर चुकें है। दूसरी और कार्यरत को कोरोनाकाल में नोवर्क नोपेमेंट के बाद भी लॉकडाउन अवधि का मानदेय दिया गया। जबकि फॉलेन आउट 7 माह से वेटिंग में होने के बाद भी कुछ नहीं दिया गया। सरकार के इस एक पक्षी व्यवहार से इनके परिवार का गुजर-बसर करना मुश्किल हो गया हैं।

एसपी ने किया जिले का भ्रमण पत्रकारों ने किया स्वागत

माही की गूंज झाबुआ।

नवागत पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुमपा द्वारा थाना मेघनगर, चौकी रम्भापुर, थाना काकनवानी, चौकी मदरानी , हरीनगर, परवलिया, थाना थांदला चौकी खवासा एवं चौकी नौगांवा का भ्रमण कर पुलिस अधिकारियो एवं कर्मचारियो से भेंट की गई एवं अपराधो के संबंध में तथा क्षेत्र की जानकारी दी। साथ ही सभी अधिकारियो एवं कर्मचारियो को जनता की समस्या का त्वरित निराककरण करने के निर्देश दिये। इसी समय पुलिस अधीक्षक श्री गुप्ता का थाना मेघनगर पर पत्रकारो द्वारा स्वागत किया गया।

ऑनलाईन ई-विशेष लोक अदालत 4 जुलाई को

माही की गूंज झाबुआ।

कोरोना काल में नवीन दूरसंचार टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर लगभग सभी कार्य ऑनलाईन इंटरनेट वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से संपन्न किये जा रहे है। इसी क्रम में जिला न्यायालय झाबुआ में 4 जुलाई को जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेश गुप्ता के मार्गदर्शन में ऑनलाईन ई-विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष लोक अदालत में मोटर (एक्सीडेंट) दुर्घटना, दावा क्लेम क्षतिपूर्ति के मामले सुनवाई के लिए रखे जावेगे एवं वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से पक्षकारों एवं बीमा कंपनियों के अधिवक्ताओं से सुलह समझौते के आधार पर मामलों का निराकरण किया जावेगा। इस उद्देश्य से विशेष न्यायाधीश श्री महेश शर्मा को विशेष लोक अदालत का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिनके द्वारा झाबुआ जिला न्यायालय में अन्य सभी न्यायालयों के क्लेम प्रकरणों की सुनवाई की जावेगी। इसी संबंध में पूर्व तैयारी के लिए पिछले दिन अधिवक्ता संघ झाबुआ के साथ क्लेम प्रकरणों से संबंधित सभी अधिवक्ताओं ने अपर जिला न्यायाधीश/सचिव श्री राजेश देवलिया के साथ विचार-विमर्श कर अधिक से अधिक क्लेम प्रकरण ऑनलाईन वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से निराकरण कराने के लिए चर्चा की गई।

अधिवक्ताओं की हुई बैठक।

प्रदेश में किल कोरोना अभियान की शुरूआत, डोर -टू-डोर होगा सर्वे

माही की गूंज बड़वानी

कोविड-19 के व्यापक सर्वेलेन्स के लिए प्रदेश भर में 15 दिवसीय किल कोरोना अभियान चलाया जायेगा। इसकी शुरूआत एक जुलाई से प्रारंभ की गई है, अभियान 15 जुलाई तक चलेगा। प्रदेश के सभी जिलो में वायरस नियंत्रण और स्वास्थ्य जागरूकता अभियान में सरकार और समाज साथ-साथ कार्य करेंगे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आमजनो से अपील की है कि, किल कोरोना अभियान में घर-घर पहुंच रहे सर्वे दल को आवश्यक जानकारी देकर सहयोग करें। सर्दी-खांसी जुकाम के साथ डेंगू, मलेरिया, डायरिया आदि के लक्षण पाए जाने पर भी जरूरी परामर्श और उपचार नागरिको को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इन कार्यों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने का आग्रह किया है।

देश के इस अनूठे हॉट बड़े अभियान से अन्य प्रदेशो तक भी एक सार्थक संदेश पहुँचेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री चौहान ने कमिश्नर-कलेक्टर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निर्देश दिए थे कि किल कोरोना अभियान के लिए आवश्यक तैयारियाँ प्रारंभ की जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि, कोरोना वायरस को समाप्त कर ही चैन की सांस लूँगा। इसे अमली जामा पहनाने के लिए राज्य सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य मिशन के वरिष्ठ अधिकारियो द्वारा अल्प अवधि में ही यह तैयारी की गई है।

डोर-टू-डोर होगा सर्वे

किल कोरोना अभियान में डोर टू डोर सर्वे के लिए पूरे प्रदेश में 11 हजार 458 सर्वे टीम लगाई जायेंगी। प्रत्येक टीम को नॉन कान्टेक्ट थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और जरूरी प्रोटेक्टिव गियर उपलब्ध कराया जायेगा।

सार्थक एप में संदिग्ध मरीजो की होगी प्रविष्टि

किल कोरोना अभियान में सर्वे द्वारा एसएआरआई, आईएलआई के संदिग्ध मरीजो के साथ-साथ मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि के संदिग्ध मरीजो को भी चिन्हित कर इनकी प्रविष्टि सार्थक एप में की जायेगी। कोविड-19 के संदिग्धो की जिनकी प्रविष्टि सार्थक एप पर की जाती है, के सम्बन्धित क्षेत्रों को मेप्ड एमएमयू द्वारा सेम्पलिंग की जायेगी। रोजाना चिन्हित किये गये संदिग्धो की सेम्पलिंग के बाद उनकी टेस्टिंग आरटीपीसीआर और टीआरयूएनएटी के माध्यम से की जायेगी।

3 लाख ये ज्यादा होगे सेम्पल

प्रदेश भर में एसएआरआई, आईएलआई सर्वे के बाद चिन्हित संदिग्धो के 3 लाख से ज्यादा सेम्पल लिये जायेंगे। रोजाना 21 हजार टेस्ट किये जाने की क्षमता विकसित की जा रही है। इसमें प्रदेश के औसत पॉजीटिविटी से अधिक पॉजीटिविटी वाले 13 जिलो में सघन सेम्पलिंग आरटीपीसीआर. और टीआरयूएनएटी के जरिए होगी। ऐसे 29 जिले जहां पाजीटिविटी दर प्रदेश के औसत से कम है, में जनरल सर्वेलेन्स के लिए पूल्ड सेम्पलिंग के निर्देश दिये गये हैं। प्रदेश में 69 टीआरयूएनएटी. साईट्स संचालित है, जहां जिला स्तर पर टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि, किल कोरोना अभियान के बाद प्रदेश में टेस्ट प्रति मीलियन की संख्या 4022 से बढ़कर 7747 हो जाने की संभावना है, जो कि, राष्ट्रीय औसत से अधिक है, इसी तरह अधिक सेम्पलिंग के परिणामस्वरूप प्रदेश की पॉजीटिविटी दर में भी गिरावट आयेगी।

पुत्री की शादी में बिना अनुमति व अधिक मेहमान बुलाना पड़ा महंगा-प्रशासन ने की कार्यवाही

माही की गूंज, बड़वानी

थाना बड़वानी पुलिस ने शनिवार को धारा 144 का उल्लंघन करने पर राठौड धर्मशाला झामरिया गार्डन बड़वानी में बिना अनुमति शादी समारोह का आयोजन कर 150 के करीब व्यक्तियो की भीड इकट्ठा करने पर मोतीलाल राठौड के विरुद्ध धारा 188 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। वर्तमान समय में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिये धारा 144 लागु है कोई भी आयोजन या समारोह बिना अनुमति के नही किया जावे तथा अनुमति के साथ 50 व्यक्ति से ज्यादा मेहमानों की उपस्थिति भी नहीं होना चाहिए, फिर भी मोतीलाल पिता तुलसीराम राठौड निवासी कचहरी रोड बडवानी के व्दारा बिना अनुमति के अपनी पुत्री आयुषी का विवाह समारोह राठौड धर्मशाला झामरिया गार्डन बड़वानी मे आयोजन कर करीबन 150 के करीब व्यक्तियो की भीड इकट्ठा कर सोशल डिस्टेन्सिंग भी नही रखी गई तथा धारा 144 का उल्लंघन कर आरोपी मोतीलाल राठौड द्वारा कलेक्टर बडवानी के व्दारा जारी धारा 144 का उल्लंघन करते पाया जाने से आरोपी मोतीलाल राठौड के विरुद्ध अपराध धारा 188 भादवि एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 का पंजीबद्ध किया गया। थाना प्रभारी टी.आई श्राजेश यादव ने बताया कि धारा 144 का उल्लंघन करने वालो के खिलाफबड़वानी पुलिस की कार्यवाही की गई और आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी।

राजनितिक प्रभाव के साथ भाजपा जिला महामंत्री के पति ने शासकीय जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण का कार्य किया शुरू

माही की गूंज, भीकनगांव (खंडवा)

भाजपा की खंडवा जिले की महामंत्री के पति ने शासकीय भूमि पर कब्जा कर लिया। भीकनगाव तहसीलदार को भाजपा की जिला महामंत्री के पति जो की एक शासकीय कर्मचारी है परन्तु सत्ता एवं पत्नी के प्रभाव के साथ शासकीय जमीन पर कब्जा कर मकान बनाने की कोशिश की गई है की शिकायत विनीत बार्चे ने की है। जिला महामंत्री श्रीमति नंदा ब्राम्हाणे के पति रुमालसिंह जिन्होंने राजनितिक प्रभाव के साथ शासकीय भूमि पर कब्जा कर लिया है से जब जानकारी ली कि, आप किस आधार पर यहां पर मकान बनाने की कोशिश कर रहे है, क्या आपके पास कोई दस्तावेज है? रुमालसिंह ने कहा हां हमारे पास प्रमाणित दस्तावेज है, हमने दस साल से 25 बॉय 50 के प्लाट का कब्जा कर इस प्लाट का दंड भरा है। इस संबंध में कस्बा पटवारी सोलंकी से चर्चा की तो हमारे पास इनकी दंड की भी कोई रसीद उपलब्ध नही है बताया। भीकनगाव तहसीलदार देवकुवरबाई सोलंकी ने बताया कि, हमे शिकायत मिली है जिसका हमने कुट परीक्षण कराने के आदेश हमारे कर्मचारी को दिए है. हमारे पास दस्तावेज आने के बाद कारवाई की जाएगी।

एक डाक्टर, जिसने कोरोना की गंभीरता को समझा, जिनका हुआ प्रादेशिक सम्मान

माही की गूंज, खरगोन

हमारे समाज में डॉक्टर को ईश्वर के समान माना जाता है। डॉक्टर, जो नाडी और पल्स देखकर व्यक्ति के रोग या बीमारी का हाल मालूम कर लेता है। इस दौर में जब हमारे सामने कोरोना जैसी महामारी ने हालात बेकाबू कर दिए है। ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर और उपचार से जुड़े पेशेवर व्यक्तियों से समाज को एक नई दिशा मिले, ऐसी हर किसी को उम्मीद रहती है। कोरोना काल में जब शासन ने भी निजी डॉक्टरों से कोरोना महामारी में कार्य लेने की नहीं सोची थी, उससे पूर्व शहर के चिंतनशील डॉक्टर रविश सराफ ने इस महामारी की गंभीरता को समझा। वे ऐसे पहले निजी डॉक्टर है, जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से जिला अस्पताल में स्थित फीवर क्लिनिक और कोविड वार्ड में अपनी सेवाएं प्रारंभ कर दी थी। जब शासन की ओर से निजी डॉक्टरों का सहयोग कोरोना महामारी में लेने का आदेश हुआ, उसके बाद भी वे लगातार कोरोना काल में ऐसे मरीजों का उपचार करते रहे। लगातार 2 माह तक वे अपने परिवार से दूर रहकर होटल का भोजन लेकर कार्य करते रहे। 1 जुलाई डॉक्टर्स-डे पर न समाज बल्कि सरकार भी ऐसे डॉक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका को समझती है और उनका हृदय से आभार व्यक्त करती है। डॉ. रविश सराफ जैसे डॉक्टरों का राज्य स्तर से सम्मान किया गया, उन्हें म.प्र. शासन के स्वास्थ्य विभाग में प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने प्रशंसा-पत्र देकर खरगोन को भी गौरवांवित किया है।

पटेल को जिलाध्यक्ष किया मनोनीत

माही की गूंज खरगोन

सम्पूर्ण जिलास्तर पर व्यापक रूप से समाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं जल संरक्षण, वृक्षारोपण, जनस्वास्थ्य आदि से सम्बंधित गतिविधियों को जन सामान्य तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुचाने हेतु रचनात्मक उद्देश्यों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी देवस्वरूपानंद जी की सहमति एवं संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जैन के परामर्श से सम्भाग प्रभारी गोपाल पंचोली द्वारा उज्जवल भारत अभियान संगठन की जिला कार्यकारिणी का गठन सर्वानुमति से किया गया।

जिसमे जिगनेश पटेल को जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया, साथ ही जिला उपाध्यक्ष दिलीप चांदोरे खरगोन, सचिन गुप्ता सेगांव, मुकेश मंडलोई ऊन, सूरज गुर्जर महेश्वर, नेहा गुप्ता खरगोन, गोपाल पाटीदार पंधान्या तथा एडवोकेट अंकित मालीवाल भीकनगांव को जिला महासचिव, एडवोकेट जितेंद्र पटेल कसरावद, अशोक दुबे खरगोन को जिला संगठन महासचिव, महेंद्र सोलंकी माँगरुल को जिला कोषाध्यक्ष, अखिलेश पाटीदार धरगांव, रितेश शर्मा महेश्वर एवं ब्रजभूषण दसौंधी बमनाला को जिला सचिव, सोहन यादव नलवां एवं डॉ सलीम एहमद गोगावां को जिला सोशल मीडिया प्रभारी, साथ ही जितेंद्र पाटीदार टेमला, सुमित माहेश्वरी सनावद, विशाल सोनी भीकनगांव, विशाल होतवानी करही, धर्मेंद्र पाटीदार नान्द्रा, चेतन्य पाटीदार एवं रविन्द्र दुबे को जिला सदस्य नियुक्त किया गया। इस मनोनयन पर सर्व श्री दिगम्बर राठौर, अवतारसिंह पाल, विजय पाटीदार, सुनील पाटीदार, जितेंद्र गौड, विजय जोशी, राकेश पाटीदार, सुधीर बाथम, अनिल चौरे,

2019 में बोर्ड परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हुए पुरस्कृत

आदिमजाति कल्याण विभाग ने शंकरशाह रानी दुर्गावती पुरस्कार से बड़वानी की छात्रा भी हुई पुरस्कृत

माही की गूंज बड़वानी

आदिमजाति कल्याण विभाग ने वर्ष 2019 में माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को शंकरशाह, रानी दुर्गावती योजना में दिये जाने वाले पुरस्कारों की घोषणा की है। इसमें बड़वानी के शासकीय उत्कृष्ठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़वानी की कुमारी नेहा रावत को मेरिट सूची में चौथा स्थान प्राप्त करने पर 15 हजार रूपये का पुरस्कार मिला है। बोर्ड की परीक्षा में कक्षा 10वी की परीक्षा में सतना जिले के छात्र अमित राज कोल को प्रथम पुरस्कार के रूप में 51 हजार रूपये की राशि, शिवपुरी के छात्र दीपक भगत को द्वितीय पुरस्कार के रूप में 40 हजार रूपये की राशि, छिन्दवाड़ा की छात्रा कुमारी लता तेकाम ने तृतीय पुरस्कार के रूप में 30 हजार रूपये की राशि तथा बड़वानी के शासकीय उत्कृष्ठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की कुमारी नेहा रावत को मेरिट सूची में चौथा स्थान प्राप्त करने पर 15 हजार रूपये की राशि और मन्दसौर की कुमारी मधुबाला को पांचवा स्थान प्राप्त करने पर 10 हजार रूपये की राशि पुरस्कार स्वरूप दी गई है।

कक्षा 12वीं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी पुरस्कृत

इसी प्रकार आदिम जाति कल्याण विभाग ने माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में मेरिट सूची में उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया है। इसमें श्योपुर की कु. रूपा तिग्गा को अनुसूचित जनजाति की मेरिट सूची में प्रथम स्थान बनाने पर 51 हजार रूपये, बुरहानपुर के छात्र अंकित घाण्डे द्वितीय स्थान बनाने पर 40 हजार रूपये, सीधी के छात्र अरविंद सिंह को तृतीय स्थान बनाने पर 30 हजार रूपये, भोपाल की छात्रा कु. विशाखा पोछाटे को चतुर्थ स्थान प्राप्त करने पर 20 हजार रूपये, दमोह की कु. प्रियाशी गौंड को पांचवा स्थान प्राप्त करने पर 15 हजार रूपये और भोपाल की कु. मुस्कान घुर्वे को छटवा स्थान प्राप्त करने कर 10 हजार रूपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विभाग द्वारा प्रशस्ति-पत्र भी प्रदान किया जायेगा।

बुरहानपुर में कोरोना के 9 नए मरीज आएं

माही की गूंज बुरहानपुर।

मंगलवार को फिर कोरोना के 9 नए संक्रमित मरीज आए है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ विक्रमसिंह वर्मा ने बताया कि कोरोना मरिज में 1 पुरूष और 8 महिलाएं है। यह नए मरीज राजीव गॉधी नगर, बैरी मैदान, डॉ भीमराव आंबेडकर वार्ड, नागझीरी मोमीनपुरा और आलमगंज आदि के है। बुरहानपुर में कोरोना संक्रमित 401 मरीज हो गए है, इनमें से 23 मरीजो की मौत हुई है।

आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना में 25 करोड़ का प्रावधान

माही की गूंज बड़वानी।

प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना में शहरी पथ व्यवसाइयों एवं हितग्राहियों को दिये जाने वाले ऋण पर राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त ब्याज अनुदान देने की स्वीकृति दी गई है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के संचालन के लिये विभागीय बजट में 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत पथ व्यवसाइयों को दिये जाने वाले 10 हजार के लोन पर केन्द्र द्वारा दिये जाने वाले 7 प्रतिशत ब्याज, जो कि केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा, के अतिरिक्त ब्याज का वहन राज्य शासन करेगा। यह प्रावधान योजना की अवधि मार्च, 2022 तक जारी रहेगा।

बुरहानपुर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन बना औपचारिक, मुख्यमंत्री की जगह सरकार के पुतले जले

माही की गूंज बुरहानपुर।

मध्यप्रदेश के बुरहानपुर में मंगलवार को कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाने के बजाए प्रदेश सरकार का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन की औपचारिकता पूर्ण कर ली, कांग्रेस ने बुरहानपुर में भाजपा द्धारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला जलाने के जवाब में मुख्यमंत्री चौहान का पुतला जलाने की घोषणा कर पुलिस-प्रशासन की नींद उडा दी थी। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर पुलिस व प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए थे।

पुलिस की भारी मौजदूगी को देखते हुए उपनगर लालाबाग में तो कांग्रेस प्रदर्शन के दौरान पुतला नही जला पाए। बुरहानपुर में कमल टॉकिज व प्रकाश टॉकिज के सामने कांग्रेस ने प्रदर्शन कर सरकार के पुतले जलाएं। जिला काग्रेस अध्यक्ष अजयसिंह रघुवंशी ने कहा कि, प्रदेश की भाजपा सरकार के 100 दिन पूर्ण होने पर कांग्रेस ने काला दिवस मनाकर विरोध प्रदर्शन किया। 100 दिन में भाजपा सरकार के कार्यकाल में ना तो बिजली माफहुए और ना ही स्कूल फीस माफ हुई है, पेट्रोल-डीजल के दाम आसमान छू रहे है, प्रदेश में सब कामकाज बंद है, परंतु तबादला उघोग खूब चल रहा है। ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष किशोर महाजन ने कहा कि, भाजाप सरकार के कुशानस को लेकर आगे भी विरोध प्रदर्शन जारी रहेगे।

कलेक्टर पैदल एवं मोटर सायकिल के माध्यम से पहुंचे पहाड़ों पर, देखा मनरेगा का कार्य ओर जानी लोगों की परेशानी

माही की गूंज, बड़वानी

जिले में लौटे प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत कार्य उपलब्ध कराने के लिये बड़ी संख्या में कार्य प्रारंभ किये गये है। दुर्गम स्थानों एवं पहाड़ों पर चल रहे इस कार्य का निरीक्षण कलेक्टर अमित तोमर द्वारा बुधवार को किया गया। इस दौरान वे कार्य स्थल तक पहुंचने के लिये कुछ स्थानों पर मोटर सायकिल से पहुंचे तो वही वे पहाड़ो पर पैदल ही चढे।

कलेक्टर अमित तोमर ने ग्राम सावरियापानी के पटेल फल्या के पहाड़ो पर मनरेगा के संचालित कार्यो के निरीक्षण के लिये लगभग 2 किलोमीटर की सवारी ग्राम के ही इक्का जमरे की मोटर सायकिल पर बैठकर की। दुर्गम रास्तो से गुजरते हुए पहाड़ पर पहुंचे कलेक्टर ने पत्थर, चेकडेम के कार्य में संलग्न प्रवासी श्रमिक दिनेश रावलिया एवं नितिन अरहरी से भी चर्चाकर जाना की वे गुजरात के किस क्षेत्र में कार्य कर रहे थे एवं उन्हें कितनी मजदूरी मिल रही थी। इस दौरान इन प्रवासी मजदूरों ने कलेक्टर को बताया कि, वे गुजरात के दग्गड़गॉव में खेती के कार्य में मजदूरी कर रहे थे, उनके साथ लगभग गॉव के 20 लोग और भी थे। किन्तु अब वे सभी अपने ग्राम में लौट आए है और उन्हें अब यही पर पर्याप्त काम मिल रहा है। इसी प्रकार कलेक्टर ने लगभग ढेड़ किलोमीटर पैदल चलते हुए ग्राम आवली के पहाड़ पर संचालित जल संरक्षण एवं बोल्डर चेकडेम के निर्माण का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होने इस कार्य में लगे 2 सौ से अधिक मजदूरों से भी चर्चाकर उन्हें मिल रही मजदूरी के बारे में जाना। इस पर कार्य कर रहे हजारसिंह चौहान ने बताया कि, पिछले 2 सप्ताह से संचालित इस कार्य में उन्हें अभी तक 18 सौ रूपए मजदूरी के रूप में मिले है। ग्राम की पहाड़ी पर संचालित इस कार्य के कारण अब उनके ग्राम के मजदूरों को पर्याप्त कार्य मिल रहा है। कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान पाटी जनपद पंचायत के सीईओ अभिषेक त्रिवेदी एवं संबंधित इंजिनियर भी उनके साथ मौजूद थे।

कलयुगी भुआ ने वास्तविक प्रमाण छुपाकर उच्च न्यायालय में प्रोटेक्शन की कि अपील

एसपी के समक्ष अध्यक्ष के साथ समझाईश देने वाले से ही खतरा होने व सुरक्षा की कि गुहार

माही की गूंज थांदला।

यह तय है जब कोई व्यक्ति अनैतिकता का मार्ग अपनाकर अपने-आप को ही सबसे सर्वोच्च मान लेता है और फिर वह अनैतिकता के दलदल में ऐसा चला जाता है कि, उसे कहीं भी नैतिकता दिखाई ही नहीं देती है।

ऐसा ही एक मामला थांदला में देखने को मिल रहा है। बता दें कि, थांदला निवासी किशोर पडियार जो की प्यारे मियां के शराब के ठेके के समय शराब की दुकान पर सेल्समेन था। सेल्समेन के दौरान अपनी अनैतिकता के साथ सेल्समेनी में पैसा कमाकर 2003 में तात्कालिक मुख्यमंत्री उमा भारती के समय आबकारी नीति में फेर-बदल किया जाकर एकल प्रणाली शराब दुकान लाटरी के माध्यम से दी गई, जिसमें थांदला-खवासा दुकान में पार्टनरशिप की शुरुआत कर जिले के साथ राजस्थान में भी कई शराब दुकानों के शराब ठेकेदार का पार्टनर रहा, तो वही वर्तमान में भी थांदला-खवासा की शराब दुकान में ठेकेदार का पार्टनर होकर वैध की आड़ में अवैध रूप से शराब का कारोबार कर रहा है।

किशोर पडियार लंबे समय से शराब का कारोबार कर अपने अवैध कारोबार को चलाने एवं मुनाफा कमाने हेतु प्रशासनिक संरक्षण के साथ कई हथकंडे अपनाते देखा गया। क्षेत्र में एजेंडों को अवैध रूप से महंगी भाव में शराब वितरित करते, वरन कोई एजेंट शराब महंगी होने के कारण किसी अन्य क्षेत्र से थोड़ी बहुत भी शराब अवैध रूप से ले आया तो उसके विरुद्ध 50 लीटर से ऊपर का केस बनवाकर उसे जेल की सलाखों में भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे अनैतिक राह पर चलकर व कई हथकंडे अपने निजी लाभ एवं मुनाफे के लिए अपनाने वाला किशोर पडियार अपने बड़े भाई कमलेश के साथ रहकर, घर में सर्वेसर्वा है तो, वही अपने अनैतिक हथकंडो में माहिर किशोर पडियार ने अब अपने भाई, भतीजे व अपनी ही बहन जिसे भतीजे की पत्नी के रूप में बहू बनाकर लाए को हथकंडे सिखाकर अपने अनैतिक हथकंडे के साथ समाज के लोगो को भी अपने निजी स्वार्थ के चलते जैल की हवा खिलाने में कोई चूक नहीं कर रहा है।

बता दें कि, किशोर पडियार के बड़े भाई कमलेश पडियार का पुत्र हार्दिक उसके ही पिता के काका जोबट निवासी निर्भय पडियार की लड़की उर्वशी यानी रिश्ते में हार्दिक की भुआ लगती है को पत्नी बनाकर ले आया। उर्वशी व हार्दिक दोनों भुआ-भतीजे ने किशोर व कमलेश के अदृश्य सहयोग के साथ विवाह किया, परंतु विवाह के पूर्व लिखे शपथ-पत्र के साथ शपथ-पत्र की नोटरीकर्ता व विवाह करवाने वाले पंडित सभी के समक्ष अपने रिश्ते की जानकारी एवं वास्तविक प्रमाण को छुपाया गया, जो प्रमाण हिंदू विवाह एवं भारतीय संस्कृति के अनुरूप शादी करना प्रतिबंधित है और शादी कर भी लेते हैं तो वह शुन्य की श्रेणी में ही माना जाता है, जिसके कारण लड़की के माता-पिता एवं परिवार हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत इस विवाह को सामाजिक रुप से किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया। समाजजनों ने लड़की के पिता निर्भय एवं परिवार की अपील पर लडके के परिवार के साथ लड़के-लड़की को समझाइश दी कि, यह विवाह भारतीय संस्कृति व हिंदू विवाह अधिनियम के साथ सामाजिक रुप से भी इस विवाह को मान्यता नहीं है और ऐसे भुआ-भतीजे का विवाह हर किसी समाज में विश्वास का हनन करता है, के साथ समझाइश दी और लिखा-पढ़ी एवं एग्रीमेंट के साथ यह रिश्ता विच्छेद करने की सलाह दी। परंतु किशोर एवं कमलेश पडियार के सरक्षण में उक्त कलयुगी युगल ने समाजजनों की बात से इनकार कर दिया। तत्पश्चात न्यायालय खुलने पर लड़की के माता-पिता हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत उक्त विधि विरुद्ध विवाह को शुन्य करवाने हेतु कानूनी कार्यवाही मान्य न्यायालय तक जाने हेतु कर रहे हैं। लड़की के पिता ने इस कार्य हेतु भी

समाजजनो ने ज्ञापन देकर एसपी से की चर्चा।

समाजजनों से सहयोग मांगा, जिस पर समाज के अध्यक्ष के साथ ही समाज के कुछ साथीगण उक्त कार्यवाही की खानापूर्ति करने हेतु वकील के पास, लड़की के माता-पिता व परिवार के साथ जा रहे हैं। वही सामाजिक व्हाट्सअप ग्रुप पर भी समाज के कई व्यक्तियों ने इस विवाह के विपरीत अपने निजी विचार रखें। जिस पर बताया जा रहा है कि, किशोर पडियार ने अपने पुराने हथकंडे अपनाकर अपने निजी स्वार्थ सिद्ध करने हेतु अपनी बहन उर्फभतीजे की पत्नी उर्फबहू के नाम से उच्च न्यायालय इंदौर में हार्दिक के साथ भुआ-भतीजे के नाते का प्रमाण छुपाकर अपने आप को बालिक होकर हार्दिक पडियार के साथ शादी करने के मिथ्या प्रमाण पेश कर प्रोटेक्शन की मांग की।

मान्य उच्च न्यायालय के निर्देशन में एसपी झाबुआ ने उर्वशी को तलब कर न्यायालय में दायर याचिका पर बयान लिये, जिस पर समझाइश देने वाले झाबुआ-अलीराजपुर परिक्षेत्र के अध्यक्ष डाडमचन्द लोदावरा के साथ उन 8 व्यक्तियों का नाम लिखवाया जो निर्भय पडियार के सहयोगकर्ता होकर विधी विरुद्ध किए इस विवाह को कानुनी रूप से शुन्य करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं उक्त मामले को प्रमुखता के साथ माही की गूंज में प्रकाशित करने वाले पत्रकार का भी नाम लिखवाकर बताया कि, मेरे घर पर 3-4 लोग आए जिन्होंने मेरे ससुर एवं परिवार को धमकाया। वही सोशल मीडिया पर भी शादी के विरूद्ध कमेंस किए जा रहे हैं जो गलत है, लेकिन एसपी के समक्ष ये उल्लेख नही किया की वे तीन-चार लोग कौन थे जो घरपर आकर उन्हे धमकाया। खेर उर्वशी के बयान के बाद एसपी के निर्देशन में आठों के विरुद्ध व्हाट्सअप पर नोटिस जारी कर जवाब हेतु थांदला तलब किया गया।

कमलेश पडियार पुलिस पर लगा रहा आरोप, जबरदस्ती पुलिस ने बेटे व बहन रुपी बहू को किया सुपुर्द

मिथ्या प्रमाण के साथ किशोर पडियार ने हथकंडे अपनाकर बहन रूपी बहू के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर, समाज के 8 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के विरुद्ध जिस तरह से अपने अनैतिक कृत्य के साथ आरोपी बनाने का प्रयास किया, उसी तरह अब अपने हथकंडे अपनाकर कमलेश पडियार अन्य प्रांत के समाज के प्रतिष्ठित एवं पदाधिकारी को घर-घर जाकर 7-8 पेज का एक प्रतिवेदन दे रहा है, जिसमें स्वयं कमलेश पडियार, लड़की के पिता निर्भय को अपना काका, उसकी लड़की उर्वशी को बहन, तो उसके बेटे हार्दिक के साथ भुआ-भतीजे का रिश्ता होना बतला रहा है। साथ ही इस विवाह में अपनी सहमति नहीं होकर थांदला पुलिस द्वारा बेटे हार्दिक व बहन रूपी बहू उर्वशी को जबरदस्ती दबाव पूर्वक सुपुर्द किया, जिस पर भयवश दोनों को अपने घर लाया, दर्शाया। साथ ही जिन दो लड़कियों से कमलेश ने हार्दिक का सम्बन्ध जोड़ा था, उनका विवाह के पुर्व संबंध विच्छेद होने के उल्लेख के साथ जिनका संबंध सगाई के बाद छुट गया व अन्यत्र उन लड़कियों का विवाह संबंध जुड़ गया है, बावजूद कमलेश पडियार उन दो लड़कियों की भी मान-प्रतिष्ठा को समाज में गिराने के प्रयास के साथ मय फोटो फ्रूफके सगाई के बाद हार्दिक के साथ विच्छेद हुए सम्बंध उन लड़कियों के फोटो हार्दिक के साथ होकर घर-घर जाकर दे रहा है। कमलेश के उक्त कृत्य पर मेवाडा कलाल समाज अध्यक्ष डाडमचन्द लोदावरा ने कहा कि, जिस किसी लड़के से सगाई संबंध हुआ, जिसका संबंध शादी के पूर्व ही टूट गया हो, जिसका कारण कुछ भी रहा हो, पर न ही हमारा समाज और न ही कानून इस बात की इजाजत देता है कि, इस तरह से जिन लड़कियों का संबंध जो कि अपनी बेटी तुल्य है और संबंध छुटने के बाद अन्य स्थान पर संबंध हो जाने के बाद, इस तरह से अपने बेटे हार्दिक के साथ खींचे फोटो को समाज में प्रचलित कर उन दोनों बेटियों की मान प्रतिष्ठा, को खत्म करने का प्रयास कमलेश द्वारा किया गया है, जिसकी पूरा मेवाड़ा कलाल समाज निंदा करता है।

लड़की के पिता निर्भय पडियार व उनकी पत्नी ने बताया कि, समाज में कमलेश पडियार प्रतिवेदन देकर स्पष्ट रूप से कह रहा है कि, मेरी बेटी उर्वशी उसकी बहन व उसके बेटे की भुआ लगती है और पुलिस के दबाव में आकर उनकी बिना मर्जी से उनके घर मेरी बेटी को बहू बनाकर ले गए हैं, पुलिस ने किस आधार पर मेरी बेटी को जबरदस्ती दबाव डालकर उनके सुपुर्द की है, अगर जबरदस्ती उनके सुपुर्द हमारी बेटी को की है तो तय है, हमारी लड़की को कमलेश एवं किशोर पडियार परिवार से जान का खतरा है। मैं उक्त विवाह को शून्य कराने की प्रक्रिया के साथ ही मेरी बेटी की सुरक्षा हेतु कमलेश पडियार के प्रतिवेदन अनुसार पुलिस से गुहार करूंगा, बेटी उर्वशी को कुछ भी जान-माल का खतरा होता है तो उसका जवाबदार हार्दिक के साथ कमलेश, किशोर पडियार व परिवार रहेगा।

समाजजनों ने एसपी को दिया ज्ञापन

उक्त मामले में सोमवार को लडकी के माता-पिता के साथ समाजजनो ने थांदला में एसपी को ज्ञापन दिया, ज्ञापन में बताया की उर्वशी ने उच्च न्यायालय में वास्तविक प्रमाण छुपाकर मिथ्या साक्ष्य के साथ बालिक होने का हवाला देकर समाजजनो को परेशान करने हेतु समाज के प्रतिष्ठीत जिन्होने इस मामले में कभी किसी को नही धमकाया न कभी धमकाएगे समाजजनो ने समझाईश के साथ दोनो परिवार में लडकी के माता-पिता अनुसार उक्त रिश्ता विच्छेद होकर आपसी में सुलह हो जाए का प्रयाश किया है, जिसके विपरीत झुठे आरोपो के साथ समाज के प्रतिष्ठीत व्यक्तियो के विरूद्ध झुठे बयान देकर कार्यवाही कि जा रही है जिसकी निषपक्ष जाच कर कार्रवाई करने की मांग की। एसपी श्री गुप्ता ने निष्पक्ष जाच करने की बात कही साथ ही व्यक्तिगत रूप से समाजजनो को कहा कि, मैने भी लॉ पढा है हिन्दु विवाह के अर्न्तगत ऐसे विवाह शून्य माने जाते है और मान्य न्यायालय में जाने के बाद लडकी के माता-पिता को न्याय अवश्य मिलेगा।

जिला चिकित्सालय में बढ़ती अस्वस्थाओं के चलते मरीजों को होना पड़ रहा परेशान

माही की गूंज झाबुआ।

जिला चिकित्सालय मे असुविधाओ का अंबार दिनो दिन बढता जा रहा है ऐसे मे ग्रमीण क्षेत्रो से आने वाले दूर दराज से मरिजो को इसका खामियाजा भूगतना पडता है। जिसमे जिला चिकित्सालय में अलसुबह से ही चिकित्सक अपनी कूर्सी से नदारद दिखाई देते है। वही मरिजो को उनका घंटो बैठकर इंतजार करना पडता है, बावजूद इसके अन्य किसी चिकित्सक को दिखाने के उनके पास कोई ओर चारा नही बचता है। ऐसे मे कई बार देखा गया है कि, सीनीयर चिकित्सक अपने ड्यूटी क्षेत्र से करीब 12 बजे ही अपने घर पहुच रहे है। जिससे की मरिजो को उनके घर जाकर अपना ईलाज करवाना पड रहा है। वही उनके द्वारा प्रायवेट मे दिखाने पर उन्हे पैसा भी अधिक लग रहा है। पूर्व मे भी कई बार अखबारो मे

चिकित्सको का आज भी बरकरार है ड्यूटी समय से पहले अपने घर जाना

यह प्रकाशित किया गया है कि, सरकारी चिकित्सक अपने ड्यूटी समय से पहले ही घर पहुच कर मरिजो को निजी क्लिनीक पर ईलाज कर अच्छा खासा पैसा वसुल रहे है। बावजूद इसके उन पर कार्यवाही होने के बजाए आज तक कोई जांच तक नही बैठी है। वही कुछ समय पहले ही सिविज सर्जन द्वारा खबर के बाद ही करीब आधे दर्जन चिकित्सको को अपनी ड्यूटी के समय से पूर्व घर पर जाने के कारण सुचना-पत्र जारी किये गये थे। जिस पर से आज तक उस बात का खुलासा नही हो पाया है कि, आखिर चिकित्सको के द्वारा जवाब क्या दिया गया। ऐसे मे साफ-साफ जाहिर होता है कि, जिला चिकित्सालय में चिकित्सको को किसका संरक्षण प्राप्त है। आखिर सब एक ही थाली के चट्टे-पट्ठे है, इसलिए क्या कार्यवाही क्या नियम।

स्वागत नही करोगे हमारा ...

पेटलावद में चोरों ने वकील और उपयंत्री के घर पर हाथ साफ किया

माधव कालोनी, महावीर कॉलोनी लगातार चोरों के निशाने पर, दहशत में जी रहे हैं रहवासी

माही की गूंज, पेटलावद

सलमान खान की सुपर हिट फिल्म दबंग का एक चर्चित डायलॉग ''स्वागत नही करोगे हमारा'' जो काफी फेमस हुआ था। कुछ ऐसा ही नए पुलिस अधीक्षक ''स्वागत नही करोगे हमारा'' के साथ हो रहा है नए एसपी आशुतोष गुप्ता के आते ही अपराधियों ने जोरदार स्वागत कर खुला चेलेंज दे दिया है, अब देखना ये है की नए साहब अपराधियों पर नकेल कसते है या बेलगाम अपराधी अपनी और से ऐसे ही पुलिस को चुनौती पेश करते रहेगे! सोमवार रात पेटलावद में चोरों से परेशान माधव कॉलोनी और महावीर कॉलोनी में बड़ी वारदात कर लाखो की चोरी को अंजाम देकर फरार हो गए। सांसद गुमानसिंह

के करीबी वकील बलदेवसिंह राठौड़ के माधव कॉलोनी स्थित सुने घर को सोमवार देर रात चोरों ने निशाना बनाकर पूरे घर पर हाथ साफकर दिया, राठौड़ का परिवार अपने गृहग्राम बरवेट में विवाह समारोह में शामिल होने गए थे। माधव कॉलोनी से लगी हुई महावीर कॉलोनी एमपीईबी के उपयंत्री वीरेंद्र सोलंकी के सुने घर मे चोरों ने हाथ साफकर दिया। वीरेंद्र सोलंकी से जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि, कुछ नगदी ओर चांदी के सिक्के चोरी हुए हैं और बाकी नगदी ओर रकम खोजने के लिए अलमारी आदि तोड़कर नुकसान पहुँचाया है। चोरी की घटना की जानकारी सुबह आसपास के लोगो ने घर के दरवाजो को खुले देखकर परिवार और पुलिस को सूचना दी, एफएसएल की टीम ने मौके पर जाँच की। वारदात के बाद से नगर में दहशत का माहौल हैं। इससे पहले भी कई चोरी की वारदात माधव कॉलोनी और महावीर कॉलोनी में हो चुकी है लेकिन पुलिस अपराधियों तक नही पहुँच सकी हैं। इस बार चोरों ने सांसद के करीबी के यहाँ वारदात को अंजाम दिया है, तय है पुलिस पर चोरी ट्रेस करने का भारी दबाव होगा जिससे कई और चोरी की वारदातों के खुलासे होने की संभावना भी है। कुछ माह पूर्व इस महावीर कॉलोनी में इस मकान के आसपास ही विकास जैन के मकान पर लाखों की चोरी को अंजाम दिया गया था, उन चोरों का आज तक पता नही लगा है। बीते कई दिनों से चोर माधव कॉलोनी, महावीर कॉलोनी, माही कॉलोनी में छोटी-मोटी वारदाते ओर मकान के ताले तोड़ने की घटनाएं हो चुकी है, थाने पर भी आवेदन दिए गए लेकिन कोई कार्यवाही नही की गई। उपयंत्री के घर से लगभग 30 से 40 हजार की चोरी बताई जा रही है। जबकि वकील बलदेवसिंह राठौड़ ने अपने घर से 30 तोला सोना और 1 लाख 26 हजार नगद चोरी होने की बात कही है, वही मामले में पुलिस फिलहाल चोरी की रकम को लेकर सही जवाब नही दे रही हैं।

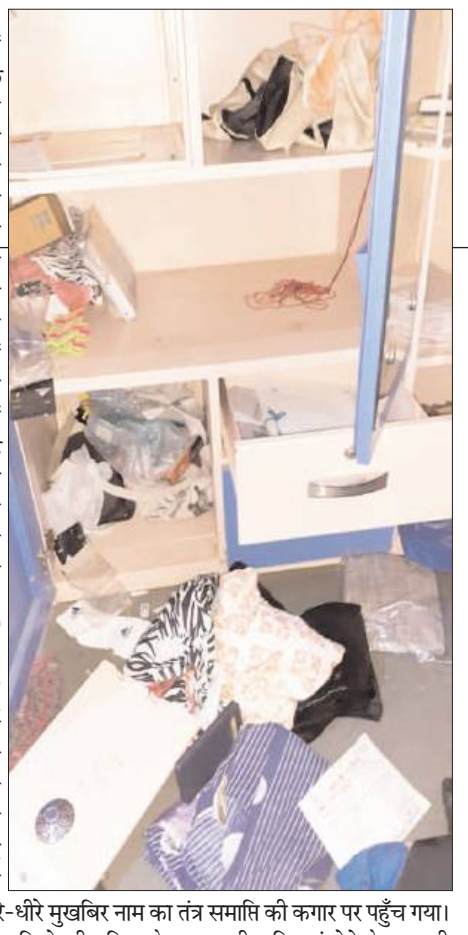

पुलिस के मुखबिर हुए खत्म, टेक्नोलॉजी में भी पीछे झाबुआ पुलिस

एक समय था जब पुलिस के पास मुखबिर की फौज हुआ करती थी, किसी भी बड़े अपराधों में 24 घंटो में नाम सामने आ जाते थे लेकिन बदलते समय के साथ पुलिस की कार्यप्रणाली लगातार इतनी गिर गई कि, मुखबिरों के नाम अपराधियों तक पहुँचने लग गए और धीरे-धीरे मुखबिर नाम का तंत्र समाप्ति की कगार पर पहुँच गया। वही टेक्नोलॉजी की बात करे तो झाबुआ जिले की पुलिस के पास सारी सुविधाएं होने के बाद भी टेक्नोलॉजी का उपयोग न के बराबर किया जा रहा है या ये भी कहा जा सकता हैं कि, अपराध होने के दो-चार दिन बाद पुलिस की रुचि लगभग समाप्त होकर थानों पर हो रही भंझगड़ी पर लौट जाती है। नए एसपी साहब के सामने अब अपनी पुलिस को अपडेट करने की बड़ी चुनौती होगी वही गंभीर अपराध और वारदातों के लिए एक पुलिस टीम का गठन करना होगा जो अपराध का खुलासा करने और अपराधियों को पकड़ने में सक्षम हो।

आदिवासी भील समाज सुधारक संघ ने जयस के खिलाफ दिया ज्ञापन

माही की गूंज झाबुआ

आदिवासी भील समाज सुधारक सघं ने गुरुवार को जयस पर हिन्दुविरोधी गतिविधिया सचांलित करने का आरोप लगाते हुए जयस के खिलाफ राज्यपाल के नाम क्लेक्टर प्रबल सिपाहा को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में जयस एक वामपंथी विचारधारा ओर मिशनरियों द्वारा पोषित सगंठन होने एवं आदिवासी समाज की संस्कृति को गलत तरीके से परिभाषित करने जेसे गंभीर ओराप लगाये ।ओर सगठन द्वारा सोशल मिडिया के माध्यम से आदिवासी समाज को भ्रमित ओर भडकाया जा रहा है। झाबुआ जिले में आदिवासी समाज ओर अन्य वर्गो के बीच शान्ति भाईचारा ,सद्भाव को बिगाडने की कोशिश की जा रही है।एवं धर्मान्तरण को रोका जावे। इसके अलावा मिशनरियों द्वारा अवेध चर्च बना कर आदिवासी समाज की भुमि पर कब्जा किया जा रहा है, उसे रोकने की मांग की गई।

स्टैण्डिग कमेटी की बैठक आयोजित हुई

माही की गूंज झाबुआ।

पंचायतों तथा नगरीय निकायों की मतदाता सूची में पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए जिला स्तरीय स्टैण्डिंग कमेटी की बैठक बुधवार को कलेक्टेऊट सभा कक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रबल सिपाहा की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

श्री सिपाहा ने इस बैठक में पंचायतों तथा नगरीय निकायों की फोटो युक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुर्ण निरीक्षण कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी और निर्वाचन आयोग के निर्देशों से अवगत कराया, नगर पालिका तथा ग्राम पंचायत की प्रारूप मतदाता सूची का नगर पालिका वार्ड, ग्राम पंचायत एवं अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिपाहा ने समिति के सदस्यों से कहा कि, वे मतदाता सूची के शुद्धिकरण के कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान करें ताकि मतदाता सूची में त्रुटि न रहे। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व झाबुआ एमएल मालवीय, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल भाना, तहसीलदार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, राजनैतिक दलों के पदाधिकारी, पार्षदगण तथा समिति के सदस्य उपस्थित थे।

ग्रामीणों का आरोप-पंचायत ने निर्माण कार्य किये नही ओर फर्जी बिल लगाकर निकाल ली राशि

भ्रष्टाचार का पर्याय बनी संजेली तेजा भीमजी साथ पंचायत

माही की गूंज, खच्चरटोडी(मेघनगर) विकास साबलिया

मेघनगर जनपद के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायत संजेली तेजा भीमजी साथ में सरपंच-सचिव ने भ्रष्टाचार की चरम सीमा को पार कर दिया। इस पंचायत में स्वीकृत हुए विकास कार्यो में भारी अनियमितता एवं भ्रष्टाचार किया गया। इस पंचायत के सरपंच-सचिव ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए पंचपरमेश्वर, ग्राम स्वराज, 14 वित्त आयोग की राशि को पंचायत के विकास कार्यो मे न लगाकर भ्रष्टाचार रुपी तिजोरी में ठिकाने लगा दी। पंचायत में सीसी रोड, पुलिया निर्माण स्वीकृत हुए लेकिन निर्माण कार्य आधा-अधुरा होकर 10 प्रतिशत भी कार्य नही किया ओर फर्जी तरीके से राशि आहरण कर ली। इसका खामियाजा यहा की ग्रामीण जनता को उठाना पड रहा है। बारिश मे सीसी रोड नही होने के कारण ग्रामीणजन कीचड मे चलने को मजबूर होगे। पंचायत मे हुए भ्रष्टाचार की जानकारी लगने पर यहा के ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियो से लेकर वरिष्ठ अधिकारियो तक पंचायत में हुई लाखो के भ्रष्टाचार की शिकायत की लेकिन कार्रवाई तो दुर की बात जांच तक नही की गई। ग्रामीणो का कहना है कि, गांव के स्थानीय युवा केलाश निनामा ने जब पंचायत दर्पण से अपनी पंचायत के स्वीकृत विकास कार्यो की जानकारी निकाली तो सब चोक गए। पंचायत में जो कार्य कभी हुए ही नही ओर उन कार्यो के फर्जी बिल लगाकर सरपंच-सचिव ने राशि आहरण कर ली। पंचायत में 5 से 6 सीसी रोड आज भी आधे अधुरे ही पडे है, लेकिन सीसी रोड पुरा बताकर राशि निकाल ली, वही मंगलिया के घर से जोगी गणावा के घर तक 3 लाख 12 हजार का सीसी रोड सह नाली निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ लेकिन मोके पर आज तक रोड नही है, पर फिर भी इस रोड के नाम से रेत, सीमेंट, गिट्टी के फर्जी बिल लगाकर राशि आहरण कर ली गई। खजुरी वाला नाले में मात्र पाईप डाले गए।

जिसका खामियाजा इस पुलिये से गुजरने वाले ग्रामीणों को उठाना पड रहा है। सीमेंट, रेत, गिट्टी का उपयोग नही होने के बावजुद इन सामग्री के फर्जी बिल बनाकर इस पुलिये की स्वीकृत 3 लाख 50 हजार की राशि निकाल ली, इसके अलावा कार्यालयीन व्यय के नाम पर भी बिल बनाकर राशि निकाल ली गई, यहा तक की सासंद निधि, विधायक निधि की राशि को भी भ्रष्टो ने मिलीभगत के साथ बिना विकास कार्य के ही राशि आहरण कर ली।

भ्रष्टाचार की सीएम हेल्पलाईन पर शिकायत पर नही हुई कार्रवाई

केलाश निनामा और ग्रामवासियों का कहना है कि, पंचायत में हुए भ्रष्टाचार की जांच कर सरपंच-सचिव पर कार्रवाई के लिए कई शिकायत हुई, कुछ समय पहले सीएम हेल्पलाईन पर भी शिकायत की थी लेकिन आज तक कार्रवाई तो दुर की बात पंचायत में आकर मोके पर किसी प्रकार की कोई जांच तक नही की गई। यह सब देखकर अब कही न कही शिकायत का निराकरण नही होने से जनता का सीएम हेल्पलाईन से भी भरोसा उठता जा रहा है।

क्लेक्टर से की शिकायत

संजेली तेजा भीमजी साथ पंचायत में सरपंच-सचिव द्वारा किये गये भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामवासियों ने मिलकर क्लेक्टर प्रबल सिपाहा को भी इसकी शिकायत की, कलेक्टर ने भी जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन रूपी झुन-झुना दे दिया। इस सम्बंध में जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन ने गूंज को बताया, मैं अभी आया हु यदि सजेली तेजा भीमजी साथ मे सरपंच-सचिव ने काम नही किया ओर फर्जी बिल लगाकर पैसे निकाल लिये तो तत्काल जांच करवाकर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। अब देखना है साहब कार्रवाई करते है या पुर्व सीईओ साथी कि तरह अपना काम करते है।

पेटलावद-थांदला राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ एक्सीडेंट

घायलों को ईगल दीप की एम्बुलेंस से तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाया गया

माही की गूंज, पेटलावद

पेटलावद से लगभग 12 किलोमीटर दूर दो कार की भीडंत से खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। दो कार के बीच हुए एक्सीडेंट मे घायलों को ईगल दीप की एम्बुलेंस से तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया, इसमें ईगल दीप मेनेजर गोपी दुबे, दिनेश पडियार, गोलू हामड, पिंटू टेलर और दीपक पड़ियार ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

फ्री डाउनलोड करें पीएससी का स्कोरकार्ड

माही की गूंज, बड़वानी

प्राचार्य डॉ. आर. एन. शुक्ल के मार्गदर्षन में वर्क फ्राम होम के अंतर्गत निरंतर कार्यरत शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी के स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्षन प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं प्रीति गुलवानिया और राहुल मालवीया ने बताया कि मध्यप्रदेष लोक सेवा आयोग द्वारा 12 जनवरी, 2020 को राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी। जो अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित हुए थे उन्हें कितने अंक प्राप्त हुए हैं, यह जानने के लिए वे आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर कार्ड फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उनके रोल नंबर और जन्म तारीख की आवष्यकता होगी। जो अभ्यर्थी अपनी ओएमआर शीट भी डाउनलोड करना चाहते हैं उन्हें इसके लिए निर्धारित शुल्क देना होगा। आयोग द्वारा यह सुविधा 29 जून से 29 सितम्बर, 2020 तक तीन माह उपलब्ध रहेगी।

कॅरियर काउंसलर डॉ. मधुसूदन चौबे ने कहा कि, जाहिर है की मुख्य परीक्षा 29 सितम्बर के बाद ही होगी। अपना स्कोर कार्ड देखने के बाद अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। इस संबंध में कोई भी मार्गदर्शन चाहिए तो कॅरियर सेल से ऑनलाइन संपर्क करें।

नए चौकी प्रभारी के आते ही चोर हुए सक्रिय, दो बाइक चोरी

माही की गूंज, खवासा

खवासा चौकी पर नए चौकी प्रभारी के रूप में रमेश कोली ने पदभार संभाले एक सप्ताह भी नहीं हुआ था की सोमवार को चोरो ने अपना जादू बताकर चोरी को अंजाम देकर एक घर का ताला तोड़ने के साथ ही दो बाईक चोरी को अंजाम रात्रि में दे दिया। जानकारी अनुसार चंदन चंद्रावत के मकान के दरवाजे का ताला तोड़ दिया पर चंदन चंद्रावत के मकान में 2 दरवाजे होने के कारण चोरो ने आगे वाला ताला तोड़ने में सफल हो गए, परंतु दूसरा ताला तोड़ने में सफल नहीं हो पाए, बताते है की चंदन चंद्रावत का पूरा परिवार बहार गया हुआ था। चोरो ने चंदन चंद्रावत के मकान में चोरी करने में असफल होने के बाद उसी खवासा बस स्टैंड के समीप हरिजन मोहल्ले की गली में राहुल पिता गोपाल चंद्रावत की एमपी 11 एमएफ9318 बाइक व पंकज डामर बामनिया की बाइक जो कि आशीष पिता नारायण निनामा से खरीदी थी जो वर्तमान में उसी के नाम से दर्ज है एमपी 45 एमक्यू 1713 के साथ चोरो ने दो बाइक का लॉक तोड़कर रफूचक्कर हो गए। खवासा पुलिस के लिए यह बड़ी चुनौती है कि, बस स्टैंड के समीप गश्त के दौरान भी चोरो ने अपनी जादूगरी बताकर चोरी को अंजाम दे दिया पर पुलिस उन चोरो तक पहुंच पाएगी या नहीं? या फिर चोरो ने पुलिस की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह लगाकर फिर चोरी को अंजाम देने में आगे भी सफल होंगे? का सवाल चर्चा में चल रहा है।

बिना पाइप लाईन और टंकी बनाए निकाल लिए पंचायत ने दस लाख

काजबी पंचायत पर शिकायतों के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई

माही की गूंज, पेटलावद

ग्राम पंचायतों में हो रहे भ्रस्टाचार के खेल का एक ओर सनसनीखेज मामला सामने आया है, रायपुरिया क्षेत्र की काजबी पंचायत में लगभग दस लाख रुपये की लागत से ग्राम पंचायत के अलग-अलग गाँव मे पानी की व्यवस्था के लिए पाईप लाइन और टंकी बनाने का कार्य करना था लेकिन पंचायत ने जमीन पर एक रुपए का काम नही किया और फर्जी बिल लगा कर पूरी राशि निकाल ली, मामले की दस से ज्यादा शिकायतें अधिकारियों तक पहुँच चुकी है, लेकिन किसी के कान में जु तक नही रेंगी और सब अपना-अपना हिस्सा लेकर बाहर होते गए और शिकायतकर्ता कार्रवाई के लिए ओर ग्रामीण सुविधा के लिए आज भी भटक रहे हैं। मामले की जानकारी पोर्टल पर अपलोड जानकारी निकलने पर मिली कि, ग्राम पंचायत काजबी ने मातापाड़ा गाँव मे 1 लाख 48 हजार, पनाश गाव में 1 लाख 42 हजार, लालरुंडी गाव में 2 लाख 44 हजार रुपए ओर काजबी में 1 लाख 80 हजार रुपये की पानी की पाइप लाईन ओर टंकी बनाने के कार्य 2018 मे स्वीकृत किया और पूरा के पूरा काम कागज पर कर पूरी राशि आहरण कर ली, ग्रामीणों की शिकायत के माध्यम से बताया कि, इन चारों गाव में न तो कोई पाइप लाईन बिछाई गई और न ही कोई टंकी बनाई गई और पूरी की पूरी राशि ग्राम पंचायत के सरपंच-सचिव द्वारा आहरण कर ली गई । मामले की शिकायत ग्रामीणों ने लगभग 300 से ज्यादा हस्ताक्षर और अंगूठा निशानी कर के अधिकारियों को की लेकिन कार्यवाही तो ठीक कोई जवाबदार जांच तक करने नही पहुँचा। ग्राम काजबी निवासी हेमराज मैड़ा का कहना हैं कि, ग्राम पंचायत द्वारा केवल पाइप लाईन ही नही बल्कि अन्य कार्यो में भी भारी भ्रष्टाचार किया है, जिसकी लगातार शिकायत हम ग्रामीण करते आ रहे है पर आज दिन तक कोई अधिकारी ने इधर झांक कर भी नही देखा। यहाँ सवाल ये उठाता हैं कि, जो कार्य हुआ ही नहीं उसका मूल्यांकन कैसे हुआ? और उसका भुगतान कैसे किया गया? चूकी मामला पानी की पाइप लाईन से जुड़ा था तो पीएचई एसडीओ बघेल से जानकारी ली गई लेकिन पिएचई की ओर से इस प्रकार का कोई कार्य विभाग द्वारा नही करना बताया, पूरा काम ग्राम पंचायत काजबी ने कागजो पर निपटा कर पूरी राशि की बंदरबाट कर दी गई।

शासकीय व अशासकीय विद्यालय 31 जूलाई तक रहेगे बंद

माही की गूंज झाबुआं

कोरोना वायरस कोविड-19 व उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु विभागीय समसंख्यक आदेश 6 जून 2020 एव 8 जून 2020 द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय 30 जून तक बंद रखे जाने संबंधी निर्देश प्रसारित किये गये थे। वही इसके चलते राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि, लोक स्वास्थ्य एवं लोक हित में प्रदेश की समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय 31 जूलाई तक बंद रहेगे। इसी के साथ ऑनलाईन अध्यापन की गतिविधियाँ विभागीय आदेश 23 अप्रैल 2020 के अनुसार जारी रखी जा सकेगी।

नए नवेले एसपी को छकाती पुलिस

मामला दो भाइयों के साथ लूट का, वारदात के 8 दिन बाद भी दर्ज नही हुई एफआईआर

माही की गूंज बामनिया, गौरव भंडारी

बामनिया-रामपुरिया रोड़ पर मारुति नन्दन गोशाला के सामने 24 जून की रात सात से आठ के बीच बामनिया निवासी मनीष चाणोदीया और नवीन चाणोदिया के साथ हुई लूट की घटना के बाद से बामनिया पुलिस की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है। वारदात के 08 से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक मामले में एफआईआर दर्ज नही कर सकी हैं। लूट का शिकार हुए दो सगे भाई ने मामले की जानकारी 24 जून को ही बामनिया चौकी पर दे दी, पहले तो पुलिस से लूट का शिकार मनीष चाणोदिया को आवेदन की बिना रिसिप्ट दिए रवाना कर दिया और दो दिन तक चौकी के चक्कर लगाने के बाद मामला दर्ज करने की बजाए एफआईआर दर्ज नही करवाने के लिए दबाव बनवाया, आखिर बामनिया पुलिस की कार्यप्रणाली देख उक्त घटना की जानकारी 27 जून को एसपी को दी गई, जिन्होंने एसडीओपी पेटलावद से मामले में शिकायत करने की बात कही, लूट का शिकार मनीष चाणोदिया ने एसपी के कहने पर एसडीओपी के नाम से आवेदन बनवाकर देना चाहा तो, एसपी के आदेश को ताक में रख कर एसडीओपी बबिता बामनिया ने चौकी प्रभारी मोहनलाल सोलंकी को लताड़ लगाने का ढोंग करते हुए मामले में कार्यवाही करने के निर्देश दिए, लेकिन चौकी प्रभारी ने मोबाइल ट्रेस करने का बहाना बनाकर दो दिन का समय मांग लिया, जिसपर एसडीओपी ने पीड़ित को बिना आवेदन स्वीकार कर दो दिन रुकने का बोलकर रवाना कर दिया। अधिकारी की ढोंगी रूपी मिली फटकार के बाद चौकी प्रभारी ने बड़ी मुश्किल से आवेदन की रिसिप्ट दी और वो भी 27 जून की तारीख में, जबकि 24 जून को ही मामले की लिखित शिकायत दर्ज करा दी गई थी, 24 जून की शिकायत की रिसिप्ट मांगने पर चौकी प्रभारी ने साफ मना कर दिया। लूट का शिकार हुए मनीष चाणोदिया ने बताया कि, पुलिस लगातार

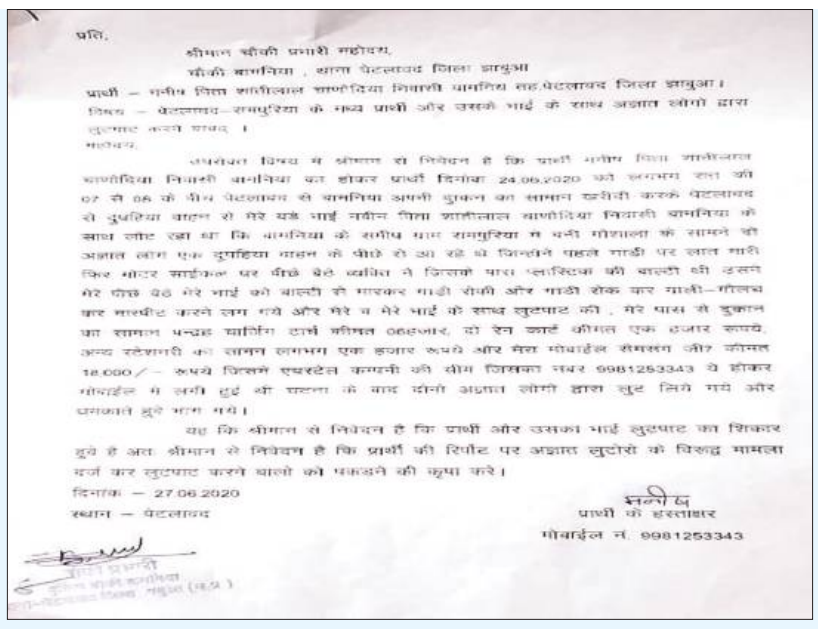

प्रति,

श्रीमान चौकी प्रभारी महोदय,
चौकी बामनिया, थाना पेटलावद जिला झाबुआ

प्रार्थी – मनीष पिता शांतीलाल चाणोदिया निवासी बामनिया तह.पेटलावद जिला झाबुआ।
विषय – पेटलावद–रामपुरिया के मध्य प्रार्थी और उसके भाई के साथ अज्ञात लोगो द्वारा लुटपाट करने संबंध ।
महोदय,

उपरोक्त विषय में श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी मनीष पिता शांतीलाल चाणोदिया निवासी बामनिया का होकर प्रार्थी दिनांक 24.06.2020 को लगभग रात्री 07 से 08 के बीच पेटलावद से बामनिया अपनी दुकान का सामान खरीदी करके पेटलावद से दुपहिया वाहन से मेरे बड़े भाई नवीन पिता शांतीलाल चाणोदिया निवासी बामनिया के साथ लौट रहा था कि बामनिया के समीप ग्राम रामपुरिया में बनी गोशाला के सामने दो अज्ञात लोग एक दुपहिया वाहन के पीछे से आ रहे थे जिन्होंने पहले गाड़ी पर लात मारी फिर मोटर साईकल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने जिसके पास प्लास्टिक की बाल्टी थी उसने मेरे पीछे बैठे मेरे भाई को बाल्टी से मारकर गाड़ी रोकी और गाड़ी रोक कर गाली–गलौच कर मारपीट करने लगे गये और मेरे व मेरे भाई के साथ लुटपाट की , मेरे पास से दुकान का सामान चप्पल चार्जिंग टार्च कीमत 08हजार, दो रेन कोट कीमत एक हजार रुपये, अन्य स्टेशनरी का सामान लगभग एक हजार रुपये और मेरा मोबाईल रेडमीनोट जीए कीमत 18,000/– रुपये जिसमें एयरटेल कम्पनी की सीम जिसका नंबर 9981253343 ये होकर मोबाईल में लगी हुई थी घटना के बाद दोनो अज्ञात लोगो द्वारा लुट लिये गये और धमकाते हुये भाग गये।

यह कि श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी और उसका भाई लुटपाट का शिकार हुये है अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात लुटेरो के विरुद्ध मामला दर्ज कर लुटपाट करने वालो को पकड़ने की कृपा करे।

दिनांक – 27.06.2020
स्थान – पेटलावद

मनीष
प्रार्थी के हस्ताक्षर
मोबाईल नं. 9981253343

एफआईआर नही करवाने के लिए दबाव बनवा रही हैं और घटना के 08 से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद भी अपराध पंजीबद्ध नही किया गया।

ऐसे हुई थी वारदात

लूट का शिकार हुए मनीष चाणोदिया ने बताया कि, 24 जून को लगभग रात की 08 बजे अपने भाई के साथ पेटलावद से सामान खरीदी कर अपने दो पहिया वाहन से लौट रहा था कि, ग्राम रामपुरिया में गोशाला के सामने पीछे से दो पहिया वाहन पर आए दो लुटेरों ने पहले तो बाईक को लात मारी ओर फिर बाइक के पीछे बैठे व्यक्ति ने जिसके हाथ मे प्लास्टिक की बाल्टी थी उससे मेरे भाई को मारा जिससे मोटरसाईकिल का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी रुक गई, दो पहिया वाहन पर मौजूद दोनो लुटेरो ने मेरे ओर मेरे भाई के साथ मारपीट कर हमारे पास से दुकान का सामान, टार्च ,रेनकोट ओर स्टेशनरी का सामान सहित 18 हजार रुपये की किमत के मोबाइल के साथ कुल 25 हजार रूपए का माल लूट कर फरार हो गए ।

रेकार्ड खराब न हो इसलिए नही करती पुलिस मामले दर्ज

यहाँ ग्रामीण इलाकों में रोज ऐसे अपराध होते है जिनको प्राथमिकता से दर्ज किया जाना चाहिए लेकिन पुलिस अपने रेकॉर्ड को साफ-सुथरा रखने के लिए छोटे-छोटे तो ठीक लूट, चोरी आदि गंभीर मामलों में भी अपराध दर्ज करने से बचती हैं। बामनिया लूट मामले की जानकारी नए एसपी तक पहुचने के बाद भी बामनिया पुलिस नए साहब को छका कर गुमराह कर रही है। मामले में चौकी प्रभारी मोहनसिंह सोलंकी का आज भी वही कहना है कि, हम मामले के दूसरे दिन कहा था, हम जांच कर लूटपाट करने वालो की खोज बिन की जा रही है। घटना के 08 दिन बाद भी मामले में अपराध पंजीबद्ध नही करने के सवाल पर चौकी प्रभारी के कोई उचित जबाब नही था ।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा, संपादक- धर्मेन्द्र पंचाल । मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई टाइटल कोड नंबर- एमपीएचआईएन-76422